राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 76 | जौनपुर शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

चक्रवाती तूफान मोंथा का तांडव, आंध्र प्रदेश – ओडिशा में 1 की मौत

केरल, (एजेंसी)। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार तड़के बताया कि आंध्र प्रदेश तट पार करने के बाद भीषण चक्रवाती तूफान मोन्था कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदल गया है, जिससे कई तटीय जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएँ चल रही हैं।आईएमडी ने सुबह 2रू30 बजे जारी अपने अपडेट में कहा, ष्तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर बना भीषण चक्रवाती तूफान मोन्था 10 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर–पश्चिम की ओर बढ़ा और कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदल गया। भीषण चक्रवाती तूफान 'मोंथा' दक्षिणी राज्य में चक्रवात का असर देखा गया, जबकि पड़ोसी राज्य ओडिशा में भी इसका प्रभाव महसूस किया गया, जहां 15 जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि चक्रवात के तट से टकराने की प्रक्रिया शाम करीब सात बजे शुरू हुई और बंगाल की खाड़ी में बनी यह मौसम प्रणाली मछलीपट्टनम और कलिंग पट्टनम के बीच काकीनाडा के आसपास आंध्र प्रदेश के तट को पार करेगी। आईएमडी के मुताबिक, चक्रवात के तट से गुजरने के दौरान हवा की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जो 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। भीषण चक्रवाती तूफान 'मोंथा' का थाई में अर्थ 'सुगंधित फूल' होता है। चक्रवात के प्रभाव से आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में मंगलवार को सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई।

नागपुर में सड़कों पर उतरे किसान, कर्ज माफी को लेकर बंद किया हाइवे

मुंबई, (एजेंसी)। महाराष्ट्र में कर्जमाफी की मांग को लेकर जारी नागपुर में किसानों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी किसान पूर्व मंत्री और प्रहार पार्टी के नेता बच्चू कडु के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को बंद किया हुआ है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को हैदराबाद से जोड़ता है। आज प्रदर्शनकारी किसानों ने ट्रेनें रोकने की धमकी दी है और रेल रोकने के लिए रेलवे ट्रैक पर पहुंच भी गए हैं। प्रहार पार्टी के नेता बच्चू कडु ने राज्य सरकार पर निशाना साधा और किसानों की कर्ज माफी करने की मांग की। बच्चू कडु ने कहा कि श्आज हम 12 बजे के बाद ट्रेनें रोकेंगे। हमारे किसान कर्ज में डूब रहे हैं। अगर राज्य सरकार के पास किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं हैं तो केंद्र सरकार को इसमें मदद करनी चाहिए।श मंगलवार को हजारों की संख्या में किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग–44 को बंद कर दिया। किसानों का आरोप है कि बार–बार वादा करने के बावजूद सरकार किसानों की कर्जमाफी नहीं कर रही है। साथ ही सूखे की समस्या से जूझ रहे किसानों को भी सरकार ने पर्याप्त मदद नहीं की है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पूर्व मंत्री बच्चू कडु ने कहा कि शकिसानों का कर्ज माफ करने की मांग थी।उन्होंने कहा कि सोयाबीन की फसल के छह हजार रुपये दिए जाएंगे और हर फसल पर 20 प्रतिशत बोनस दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में इस समय भावांतर योजना चल रही है, लेकिन यहां ऐसी कोई योजना नहीं है।

अयोध्या का विकास भव्यता, आस्था और आधुनिकता का संतुलित मॉडल बने - योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अयोध्या महायोजना 2031 से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए कहा कि अयोध्या का विकास भव्यता, आस्था और आधुनिकता तीनों का समन्वित रूप होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महायोजना का लक्ष्य अयोध्या को सुनियोजित, सुव्यवस्थित और सतत (सस्टेनेबल) विकास के साथ विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विकास कार्यों में अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक गरिमा और पर्यावरणीय संतुलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने महायोजना के बिंदुओं पर विभागीय अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि अयोध्या विजन 2047 के अंतर्गत अयोध्या को ग्लोबल आध्यात्मिक नगरी, ज्ञान नगरी, उत्सव नगरी, तीर्थ अनुकूल अवसंरचना, विविधीकृत पर्यटन, ऐतिहासिक सर्किट व हेरिटेज वॉक, हरित एवं सौर ऊर्जा आधारित नगरी के रूप में आधुनिक सुविधाओं के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह महायोजना अयोध्या के सुनियोजित, सुव्यवस्थित और सस्टेनेबल विकास की आधारशिला बनेगी।ं बैठक में बताया गया कि अयोध्या महायोजना 2031 का उद्देश्य शहर को ग्लोबल स्पिरिचुअल एवं टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना है। योजना के तहत अयोध्या विकास क्षेत्र को 18 जोनों में विभाजित कर संतुलित भूमि उपयोग सुनिश्चित किया गया है। प्रस्तावित 23. 94 लाख की अनुमानित जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए 52.56 प्रतिशत भूमि आवासीय, 5.11 प्रतिशत वाणिज्यिक, 4. 65 प्रतिशत औद्योगिक, 10.28 प्रतिशत सार्वजनिक है।

कोई सीट खाली नहीं, अमित शाह ने बता दिया कौन होगा एनडीए का सीएम

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को स्पष्ट रूप से कहा कि राजनीति में कोई सीट खाली नहीं होती। बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि सीएम या पीएम के लिए कोई सीट खाली नहीं है। इधर नीतीश कुमार हैं, उधर पीएम मोदी हैं। शाह का यह बयान विपक्षी खेमे में नेतृत्व की महत्वाकांक्षाओं को लेकर चल रही अटकलों के बीच आया है। नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री बने रहने और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बने रहने पर जोर देकर शाह ने राज्य में किसी भी राजनीतिक बदलाव या नए सत्ता समीकरण की अफवाहों पर विराम लगाने की कोशिश की। अपने भाषण के दौरान, शाह ने बिहार की छवि निखारने और पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न प्रदान करके राज्य की विरासत का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह कदम भारत के लोकतांत्रिक और सामाजिक विकास में बिहार के योगदान के प्रति केंद्र के सम्मान को दर्शाता है। केंद्र के कड़े फैसलों की सराहना करते हुए, अमित शाह ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध लगा दिया है और उसके सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बिहार की जनता से आगामी विधानसभा चुनावों में एनडीए की निर्णायक जीत सुनिश्चित करने का आग्रह किया। शाह ने कहा, ष्पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को है। क्या आप सभी हमें वोट देंगे? आइए, दरभंगा की सभी 10 सीटों पर एनडीए को जिताने का संकल्प लें। मिथिला की बेटी मैथिली ठाकुर यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और मैं लालू यादव की पार्टी को बताना चाहता हूँ ।

चिराग पासवान का ऐलान– नीतीश कुमार ही एनडीए के चुनावी नेतृत्वकता

पटना। बिहार की सियासत में सीएम फेस को लेकर चल रही अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मंगलवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही एनडीए की ओर से चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं और आगे की प्रक्रिया लोकतांत्रिक ढंग से तय होगी। चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एक ही घोषणा कितनी बार की जाएगी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं और जैसा कि गृह मंत्री पहले ही कह चुके हैं, चुनाव के बाद जो विधायक जीतकर आएंगे और वे ही मुख्यमंत्री का चयन करेंगे। यही सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि जब राजस्थान जैसे राज्यों का उदाहरण दिया जाता है तो यह नहीं भूलना चाहिए कि वहां एक ही पार्टी चुनाव लड़ रही थी,

जबकि बिहार में एनडीए के तहत पांच दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मर्यादा यही कहती है कि हर दल के विधायक को अपनी बात रखने का मौका मिले। मेरे जितने विधायक जीतकर आएंगे, वही मुख्यमंत्री के चयन का निर्णय करेंगे। उन्होंने तेजस्वी के सीएम चेहरे के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ष्लती से एक बार कुछ लोगों ने सीएम चेहरे की घोषणा कर दी तो उन्हें लगने लगा कि वे मुख्यमंत्री बन गए। नाम कैसे तय हुआ, यह सबको पता हैकृकभी आंख दिखाकर, कभी डराकर–धमकाकर नाम मनवाया गया। चिराग पासवान ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पर निशाना साधते हुए कहा, ष्आज मुकेश सहनी खुश हैं कि वे डिप्टी सीएम फेस हैं, लेकिन उनका समाज देख रहा है कि यह फैसला कैसे लिया गया। इसके लिए कितनी मिन्नतें और हाथ–पांव जोड़ने पड़े,।

प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मुंबई का दौरा ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम को करेंगे संबोधित

नई दिल्ली , (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज यानी 29 अक्तूबर 2025 को मुंबई का दौरा करेंगे। यहां शाम लगभग 4रू00 बजे, वे नेस्को एग्जिबिशन सेंटर, मुंबई में आयोजित इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से जारी बयान के मुताबिक, पीएम मोदी भारत समुद्री सप्ताह (आईएमडब्ल्यू) के प्रमुख कार्यक्रम ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की भी अध्यक्षता करेंगे। यह फोरम वैश्विक समुद्री कंपनियों के नेतृत्व, प्रमुख निवेशकों, नीति निर्माताओं, नवप्रवर्तकों और अंतरराष्ट्रीय भागीदारों को वैश्विक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य पर विचार–विमर्श करने के लिए एक

मंच पर लाता है।पीएमओ के मुताबिक यह फोरम सतत समुद्री विकास, लचीली आपूर्ति शृंखला, हरित नौवहन और समावेशी नीली अर्थव्यवस्था रणनीतियों पर बातचीत के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री की भागीदारी समुद्री अमृत काल विजन 2047 के अनुरूप महत्वाकांक्षी, भविष्योन्मुखी समुद्री परिवर्तन के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। चार रणनीतिक स्तंभों–बंदरगाह आधारित विकास, नौवहन एवं जहाज निर्माण, निर्बाध आपूर्ति शृंखला और समुद्री कौशल निर्माण–पर आधारित इस दीर्घकालिक दृष्टिकोण का मकसद भारत को दुनिया की अग्रणी समुद्री शक्तियों में शुमार करना है। 27 से 31 अक्तूबर तक महासागरों का एकीकरण, एक समुद्री दृष्टिकोण विषय पर आयोजित, भारत समुद्री सप्ताह 2025, वैश्विक समुद्री केंद्र और नीली अर्थव्यवस्था में अग्रणी के रूप में उभरने के लिए भारत के रणनीतिक रोडमैप को प्रदर्शित करता है। भारत समुद्री सप्ताह 2025 में 85 से अधिक देश भाग ले रहे हैं, जिसमें 1,00,000 से अधिक प्रतिनिधि, 500 से अधिक प्रदर्शक और 350 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हिस्सा ले रहे हैं।

मुंबई में होगा जलवायु सप्ताह, भारत के नेतृत्व को मिलेगा वैश्विक मंच

मुंबई, (एजेंसी)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि मुंबई में अगले साल फरवरी में श्मुंबई जलवायु सप्ताहश आयोजित किया जाएगा। यह जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को उजागर करने वाला एक वैश्विक सम्मेलन होगा। सतारा महिला डॉक्टर सुसाइड केस में सीबीआई जांच की मांग की मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस महत्वाकांक्षी पहल को प्रोजेक्ट मुंबई नामक संस्था की अवधारणा के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है और यह कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा बृहन्मुंबई नगर निगम के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने मंत्रालय के समिति कक्ष में आयोजित एक बैठक में इस पहल की घोषणा की। मुख्यमंत्री फडणवीस ने विश्वास व्यक्त किया कि विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन, खाद्य एवं ऊर्जा की कमी के संदर्भ में यह पहल अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। इसके साथ ही विकास एवं पर्यावरणीय कार्रवाई के बीच संतुलन स्थापित करने में प्रभावी भूमिका निभाएगी। मुझे नहीं लगा था वे भी 'पप्पूगिरी' करेंगे मुंबई जलवायु सप्ताह का मुख्य कार्यक्रम 17 से 19 फरवरी, 2026 तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शहर भर में विभिन्न प्रदर्शनियां, कार्यशालाएं, फिल्म, कला, खेल, स्वास्थ्य और अध्यात्म से संबंधित गतिविधियां और जलवायु खाद्य महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण के 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे और इसमें एक व्यवहार्य जलवायु परिवर्तन कार्रवाई कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह कार्यक्रम राज्यों के मुख्यमंत्रियों, विभिन्न शहरों के प्रतिनिधियों, उद्योग, सामाजिक संगठनों, छात्रों और युवाओं की भागीदारी से तैयार किया जाएगा। इस अवसर पर फडणवीस ने मुंबई जलवायु सप्ताह के लोगो का अनावरण किया समय सीमा छह महीने तक बढ़ी मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मुंबई जलवायु सप्ताह भारत के कार्रवाई के साथ नेतृत्व करने के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, मुंबई और महाराष्ट्र वैश्विक दक्षिण के लिए एक निष्पक्ष, नवीन और अच्छी तरह से वित्तपोषित जलवायु भविष्य बनाने में मदद करने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी कहा कि मुंबई जलवायु सप्ताह वैश्विक दक्षिण में जलवायु कार्रवाई और सहयोग के क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को साबित करने का एक प्रमुख मंच होगा।

राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने के लिए अंबाला पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार सुबह हरियाणा के अंबाला स्थित वायुसेना स्टेशन पहुंचीं, जहां से वह राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरेंगी। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान राफेल लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह समेत कई अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति भवन की ओर से मंगलवार को जारी एक बयान में कहा गया था, "राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल हरियाणा के अंबाला जाएंगी, जहां वह राफेल विमान में उड़ान भरेंगी।" सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर मुर्मू ने 8 अप्रैल, 2023 को असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन में सुखोई–30 एमकेआई लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी और वह ऐसा करने वाली तीसरी राष्ट्रपति बन गई थीं। पूर्व राष्ट्रपति ए पी जे अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल ने क्रमशः 8 जून, 2006 और 25 नवंबर, 2009 को पुणे के पास लोहेगांव वायुसेना स्टेशन से सुखोई–30 एमकेआई लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। फ्रांसीसी एयरोस्पेस कंपनी दसॉ एविएशन द्वारा निर्मित राफेल लड़ाकू विमान को सितंबर 2020 में अंबाला वायुसेना स्टेशन पर भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया था। पहले पांच राफेल विमानों को 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में शामिल किया गया था। ये विमान 27 जुलाई, 2020 को फ्रांस से यहां पहुंचे थे। पाकिस्तान के नियंत्रण वाले इलाकों में आतंकी ढांचों को नष्ट करने के लिए सात मई को शुरू किए गए'ऑपरेशन सिंदूर' में राफेल विमानों का इस्तेमाल किया गया था।

केशव प्रसाद मौर्य का दावा– बिहार की जनता तेजस्वी को सत्ता नहीं सौंपेगी

पटना , (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि एनडीए 2010 वाली सफलता को 2025 भी दोहराएगा। माहौल साफतौर पर एनडीए के

पक्ष में है और बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व के साथ मजबूती से खड़ी है।केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बिहार में एनडीए के लिए समर्थन लगातार बढ़ रहा है क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर जंगलराज वापस आया तो एक बार फिर नागरिकों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अपराधी, माफिया और दंगाई बम, पिस्तौल और एके–47 लेकर खुलेआम घूमेंगे और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि तेजस्वी यादव ने एक बार कहा था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का चेहरा हैं, और राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं से कहलवाया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद का चेहरा हैं। लेकिन लोग अक्सर श्मुंगेरी लाल के हसीन सपनेश देखते हैं। कोई खुद को प्रधानमंत्री बनते देखता है, कोई खुद को मुख्यमंत्री बनते देखता है, लेकिन जब वे जागते हैं, तो वास्तविकता वही रहती है, वे वही हैं, जो वे थे। बिहार की जनता तेजस्वी यादव के हाथों में बिहार नहीं सौंपेगी और इसे फिर से जंगलराज की आग में जलने नहीं देगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि मैं कह सकता हूं कि 2025 में एनडीए के लिए माहौल वैसा ही है जैसा 2010 में था। एनडीए यहां बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यहां न तेजस्वी यादव हैं और न राहुल गांधी, यहां चल रही है पीएम मोदी और सीएम नीतीश की आंधी। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चुनाव आयोग की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए।

महागठबंधन का घोषणा पत्र खोखले वादों का पुलिंदा – रविशंकर प्रसाद

पटना, (एजेंसी)। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन द्वारा जारी संयुक्त घोषणा पत्र को खोखले वादों का पुलिंदा बताते हुए कहा कि इसको बनाने वाले भी जानते हैं कि उनकी सरकार तो बनने वाली नहीं है, इसलिए दावे करने में क्या बुराई है? पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने घ्पटना के भाजपा मीडिया सेंटर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा कि यह घोषणा पत्र संयुक्त नहीं, तेजस्वी यादव का प्रण है। उन्होंने कहा, यह घोषणा पत्र बिहार की जनता को ऐसे लोकलुभावन तस्वीर पेश करता है, जिसमें न कोई रंग है न ही बदलाव का कोई संकल्प। बिहार की जनता भी

समझती है। तेजस्वी यादव उन्होंने कहा कि इस घोषणा पत्र में अपराध पर तो जीरो टॉलरेंस है, लेकिन भ्रष्टाचार पर कुछ नहीं कहा गया है। स्वाभाविक है कि अगर ऐसा दावा किया जाता तो बात बहुत आगे तक जाएगी। दरअसल, जो नया विजन देने का दावा कर रहे हैं, वे 420 के आरोपी हैं। राजद भ्रष्टाचार की पाठशाला है और यही उनका अतीत है, वर्तमान है और भविष्य भी होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपराध पर जीरो टॉलरेंस को लेकर कहा कि उन्हें यह भी कहना चाहिए था कि अब मुख्यमंत्री आवास से अपराधियों से बात नहीं होगी। राजद के गुंडे जो जमीन छीनते हैं, वे नहीं करेंगे। अपराध के शक की सुई जहां जाएगी, कार्रवाई करेंगे। राहुल गांधी भाजपा नेता ने कटाक्ष करते हुए कहा कि यह न राहुल गांधी का प्रण है, न महागठबंधन का प्रण है, यह मात्र तेजस्वी यादव का प्रण है। राजद के शासनकाल में बिहार का क्या हाल हुआ था, वह देश जानता है। तेजस्वी यादव के विकास कार्यों करने के दावे को लेकर उन्होंने कहा कि जो काम हुआ, वह नीतीश सरकार ने किया और आपके भ्रष्टाचार के कारण ही वे आपसे अलग हुए। उन्होंने कहा कि एनडीए का काम जमीन पर उतरा है, आगे और बढ़ेगा। भ्रष्टाचार पर खुलकर बोलने से तेजस्वी यादव डरते हैं। भाजपा नेता ने उपनिवेश बनाने को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 20 साल से एनडीए के नेता हैं और रहेंगे।

संपादकीय

छठ पर्व में राजनीति की घुसपैठ

पूर्वांचलियों के लिए महापर्व समान छठ पूजा चार दिनों की धूमधाम के साथ संपन्न हुई। बीते कुछ बरसों में बिहार और उत्तरप्रदेश के अलावा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों में भी छठ की धूम दिखने लगी है, क्योंकि इन राज्यों में बड़ी संख्या में रोजगार, शिक्षा या व्यवसाय के लिए पूर्वांचल से लोग आकर बस गए हैं। छठ पर्व में 36 घंटे का कठिन व्रत किया जाता है और व्रतियों के अलावा पूरा परिवार स्वच्छता पर खास ध्यान देता है। इस पर्व में नदियों की महत्ता, खेती का सम्मान नए सिरे से रेखांकित किया जाता है। छठ का प्रसाद घर पर ही बनता है, और इसी का वितरण सबमें होता है। अर्घ्य देने के वक्त सूप में गन्ना, मूली, कंद, सेब, केले जैसे मौसमी फल होते हैं। इस लिहाज से देखें तो दीपावली, करवा चौथ, क्रिसमस आदि के विपरीत छठ पर्व ने अब तक बाजार को अनाधिकार प्रवेश से रोक कर रखा है। हालांकि राजनीति ने लोक आस्था के इस पर्व में अपनी घुसपैठ कर ही ली है। हिंदी पट्टी पर भाजपा धार्मिक भावनाओं को भुनाते हुए ही अपना दबदबा बढ़ा पाई है। पहले ये भावनाएं राम मंदिर से जुड़ी हुई होती थीं, अब मंदिर बन गया है तो भाजपा ने अपनी रणनीति में हिंदू धर्म के पर्व त्योहारों को सियासत का जरिया बना लिया है। नवरात्रि पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व्रत और कन्यापूजा करते दिखते हैं। रामलीलाओं का हिस्सा बनते हैं। दीपावली पर अयोध्या में दीए जलाने का रिकार्ड बनने लगा है और अब दिल्ली जीतने के बाद यहां भी यह सिलसिला शुरु हो गया है। छठ पूजा पर भी दिल्ली में हलचल रहती ही थी, लेकिन इस बार बिहार चुनाव के कारण भाजपा ने मानो इसे अपना राजनैतिक पर्व मनाने के लिए इस्तेमाल किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी अर्घ्य देते नजर आईं, ताकि पूर्वांचलियों से निकटता दिखा सकें। इस बार तो राष्ट्रपति मुर्मू के अर्घ्य देने की तस्वीरें भी सामने आईं। बिहार के नेताओं के घरों पर शुरु से छठ पूजा होती रही है। लेकिन बिहार चुनावों के कारण सोशल मीडिया पर सभी ने छठ पूजा की खूब सारी तस्वीरें डालीं, ताकि जनता को बताया जा सके कि छठी मैया से उन्होंने आशीर्वाद मांगा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस बार तस्वीरों की इस प्रतियोगिता में चूक गए। उनकी तैयारी तो पूरी थी कि दिल्ली के वासुदेव घाट पर जाकर अर्घ्य वे दें और फिर उन तस्वीरों को जनता तक पहुंचाएं। भाजपा समर्थित मीडिया के कुछ एंकर्स भी वासुदेव घाट जाकर, रेखा गुप्ता का साक्षात्कार कर यह माहौल बना चुके थे कि भाजपा सरकार के आते ही यमुना नदी साफ हो गई है। लेकिन इन्हीं खबरों के बरक्स आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और कुछ पत्रकारों ने यमुना नदी की सफाई की पोल खोल दी, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी को उगते सूर्य को अर्घ्य देने और बिहार चुनाव से ठीक पहले छठी मईया के नाम पर भावनाओं को भुनाने का मौका नहीं मिला। भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी के आने को लेकर कई जगह पोस्टर–बैनर लगाए थे। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस अवसर के इंतजार में थीं कि श्री मोदी वासुदेव घाट पर डुबकी लगाते तो हाईकमान के सामने उनके अंक कुछ और बढ़ जाते। लेकिन मीडिया के एक हिस्से ने पड़ताल कर यह सच जनता के सामने ला दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक नकली यमुना बनाई गई है और उसमें साफ पानी लाकर डाला गया है। कुछ स्वतंत्र यूट्यूबर्स ने वीडियो के जरिए दिखाया कि सोनिया विहार से पानी की पाइपलाइन लाकर उसमें गंगा का पानी डाला गया। यही बात आप नेता सौरभ भारद्वाज भी कई दिन पहले से बता रहे थे। भाजपा नेताओं ने दावा किया था । कि दिल्ली में भाजपा सरकार ने यमुना को छठ पर खासतौर से साफ कराया है।

बिहार में विधानसभा चुनावों में जाति व्यवस्था या महिला सशक्तिकरण का प्रश्न?

अजय दीक्षित

बिहार विधानसभा चुनावों में जातियों का ध्रुवीकरण हो रहा है। हालांकि यह बात नई नहीं है क्योंकि बिहार देश की सामाजिक न्याय और जाति व्यवस्था की प्रयोगशाला है। केंद्रीय सरकार ने पूरे देश में जनगणना कराई है उसमें जाति गत ब्यौरा भी है। बिहार में जाति गणना के परिणाम आगये है ।अति पिछड़ी जातियों की संख्या 36.87 फीसदी है जबकि पिछड़ी जाति 27, अगड़ी जातियों 15.25 , यादव 14.89 ,मुस्लिम 17.42 फीसदी है। छोड़ी जातियों कुर्मी, निषाद, कोइरी,है ।अनुसूचित जाति 19.05 और जनजाति 1. 68 फीसदी है। कुल आबादी तेरह करोड़ से अधिक है। अगड़ी जातियों में ब्राह्मण 3.75, भूमिहार 5.25 राजपूत 3.95, वैश्य 2.12 फीसदी हैं। राजनीतिक रूप से बिहार में मगध, पटना, बेगुसराय, दरभंगा क्षेत्र है।इन क्षेत्रों में 38 जिले ,101, अनुभाग और 243 विधानसभा सीट है। मुख्य भाषाओं में भोजपुरी, मैथिली,प्रमुख हैं। बिहार विधानसभा चुनावों में जातियों के गणित को भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक दल भी नकार नहीं रहे हैं हालांकि ऐसा नहीं है कि चुनाव में बिहार में ही जाति व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक दलों ने गठबंधन किया है प्रत्येक राज्य में ऐसा होता है लेकिन उसकी सीमा होती है। महागठबंधन में राजद माई फैक्टर को लेकर चल रही है और उसका कोर मतदाता मुस्लिम और यादव है जिनका जोड़ 32 फीसदी के आसपास है। लेकिन माई फैक्टर में से यादव वोट बिखर सकता है और कुछ उम्मीदवार के हिसाब से डाल सकते हैं। लेकिन मुस्लिम मत भी नीतीश कुमार के पक्ष में जा सकता है।ह्रष्ठ की ओर से 101 सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू चुनाव लड़ रही है वहीं नीतीश कुमार के जेडीयू उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी का स्वर्ण वोट ,अति पिछड़ी जातियों का वोट मिलता रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है उसको गैर यादव पिछड़ी जातियों,स्वर्ण वोट, मिल सकते हैं लेकिन यह तय है कि मुस्लिम मतदाता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करेगा । कांग्रेस 61 सीट पर चुनाव लड़ रही है उसे मुस्लिम ,यादव,अति पिछड़ी जातियों, स्वर्ण वोट भी मिल सकता है लेकिन कांग्रेस के पास प्रचारकों की कमी है और महागठबंधन के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कोई प्रचारक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेषकर 48 फीसदी मतदाता महिलाओं में बहुत लोकप्रिय हैं।अगर अन्य राज्यों की तरह ये वोटर सक्रिय हो जाता है तो ह्रष्ठ की बढ़त निश्चित है। हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर का कहना है कि नीतीश कुमार सरकार जिन एक करोड़ महिलाओं को दस दस हजार रुपए दिए हैं स्वसहायता समूह चलाने के लिए यह मुद्दा बिहार की तीन करोड़ नब्बे लाख महिलाएं मतदाता में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। यद्यपि तेजस्वी यादव ने भी जीविका दीदियों को 3०० प्रति महीने देने का वायदा किया है अब ये चुनाव में ही मालूम पड़ता है कि किसका वायदा महिलाओं में लोकप्रिय होता है। शशि शेखर ने कहा कि राजद का कोर मतदाता यादव तेजस्वी की कमजोरी भी है क्योंकि इस तबके को बिहार का बाहुबली माना जाता है और अन्य जातियां इसके खिलाफ मतदान करती हैं। बिहार में नीतीश कुमार की इमेज भी एक फैक्टर है। उन्होंने शासकीय नौकरी में 27 फीसदी आरक्षण दिया है।इससे पुलिस बल, शिक्षा विभाग में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है।यह भी महिला सशक्तिकरण का अंग है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के नाम पर ही चुनाव जीता। झारखंड में जेएमएम ने भी यही तरीका अपनाया था। अन्य मुद्दों पर गौर करें तो यह मालूम होता है कि कानून व्यवस्था,विकास,के मामले में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद बने हुए हैं। केंदीय योजनाओं का लाभ भी जैसे प्रधानमंत्री सड़क, राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण की सड़क परियोजना, हवाई अड्डे के निर्माण कार्य में बिहार को केन्द्रीय मदद मिली है।

भाजपा की राजनीति का दारोमदार अब 'घुसपैठ- पर

अनिल

सरकार क्या सचमुच घुसपैठ की समस्या का समाधान करना चाहती है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि पिछले 11 साल से केंद्र में लगातार भाजपा की सरकार है और अभी तक उसकी ओर से घुसपैठ रोकने का एक भी गंभीर प्रयास होता नहीं दिखा है। अमित शाह पिछले छह वर्षों से देश के गृह मंत्री हैं। इस बात का

खूब ढिंढोरा पीटा जाता है उन्होंने सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने 1951 में भारतीय जनसंघ के नाम से अपनी जिस राजनीतिक शाखा का गठन किया था, उसका मुख्य लक्ष्य था– सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिये कांग्रेस का विकल्प बनना और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। इसके लिए उसके तीन प्रमुख मुद्दे थे– देश में समान नागरिक संहिता, जम्मू–कश्मीर में अनुच्छेद 370 का खात्मा और गौहत्या पर प्रतिबंध। करीब तीन दशक बाद जनसंघ के नेताओं ने जब जनता पार्टी से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का गठन किया तो उसके एजेंडे में भी ये तीन मुद्दे शामिल रहे। फिर भी इन मुद्दों से बात बन नहीं बन रही थी, सो उसने 1987 के आते–आते अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने के मुद्दे को भी अपने एजेंडे में शामिल कर लिया। यह मुद्दा उसके लिए बहुत लाभदायी रहा और इसी के सहारे वह सत्ता तक पहुंची। साल 1989 से लेकर 2024 तक हर चुनाव उसने सांप्रदायिकता की खेती करते हुए इसी मुद्दे पर लड़ा। हालांकि 2024 के चुनाव से पहले जैसे–तैसे अयोध्या में राम मंदिर भी बन गया था, इसलिए यह मुद्दा उस चुनाव में नहीं चल पाया। भाजपा न सिर्फ अयोध्या में हारी बल्कि उत्तर प्रदेश की 80 में से आधी से ज्यादा सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा। केंद्र में उसकी सरकार भी जैसे–तैसे ही बन सकी। राम मंदिर बनने से पहले ही 2019 में अनुच्छेद 370 का मुद्दा भी खत्म हो चुका था। रही बात समान नागरिक संहिता लागू करने की, तो उसके लिए कुछ कवायदें हुईं लेकिन देश भर में लागू करना कई कारणों से संभव नहीं हो सका। इसलिए राज्यों के स्तर पर उसे लागू करना शुरू किया गया। उत्तराखंड पहला राज्य बना, जहां समान नागरिक संहिता लागू हुई। उसी की तर्ज पर गुजरात, असम, मध्य प्रदेश आदि भाजपा शासित राज्यों की सरकारों ने इसे अपने यहां भी लागू करने की बात कही है। जहां तक गौहत्या पर राष्ट्रव्यापी पूर्ण प्रतिबंध की बात है, तो यह भाजपा की सरकार के लिए व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है। इसकी अहम वजह यह है कि गोमांस के वैश्विक बाजार में भारत दूसरे नंबर का सबसे बड़ा खिलाड़ी है और भाजपा के कई वित्त पोषक कारोबारी भारत में इस धंधे से जुड़े हुए हैं। इसलिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे भाजपा–आरएसएस के आनुषंगिक संगठन अपने कार्यकर्ताओं को व्यस्त रखने, समर्थकों को बहलाने और मुसलमानों को डराने–चिढ़ाने के लिए समय–समय पर यह मुद्दा उठाते रहते हैं। इससे ज्यादा उनके लिए इस मुद्दे की कोई अहमियत नहीं है। अब सवाल है कि इन मुद्दों के निबटारे के बाद आगे क्या? हिंदुत्व की ध्वजा फहराते हुए वोटों की खेती तो ध्रुवीकरण वाले किसी मुद्दे के जरिये ही हो सकती है। इस सिलसिले में लगता है कि भाजपा और आरएसएस ने अब घुसपैठ के मुद्दे को अपनाने का फैसला किया है। अब हर चुनाव में इस मुद्दे को जोर–शोर से उछाला जाएगा और इससे निबटने के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। जाहिर है कि ऐसा करते हुए घुसपैठ की समस्या के लिए कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों पर घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाएगा। यह बताने की जरूरत नहीं कि इसी मुद्दे के जरिये मुसलमानों के खिलाफ नफरत भी फैलाई जाएगी। हालांकि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि यह मुद्दा भाजपा को चुनाव जीता देने में कितनी कारगर भूमिका अदा करेगा, क्योंकि झारखंड में यह मुद्दा पिट चुका है। वहां असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को इस मुद्दे के चौंपियन के तौर पर उतार कर भाजपा ने बड़े जोर शोर से यह मुद्दा उठाया था लेकिन उसे बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी थी। इसके बावजूद भाजपा ने हार नहीं मानी है और वह बिहार विधानसभा के चुनाव में इसे आजमा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह वहां अपनी हर चुनावी रैली में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं। मोदी ने इसी साल 15 अगस्त को लाल किले से ऐलान किया था कि सरकार एक उच्च अधिकार प्राप्त डेमोग्राफी कमीशन बनाएगी, जो घुसपैठ की समस्या का आकलन करेगा और इससे निबटने के उपाय सुझाएगा। गौरतलब है कि मोदी और उनकी सरकार की चिंता के केंद्र में चीन से होने वाली सैन्य घुसपैठ कतई नहीं है, जो कि अक्सर होती रहती है– कभी अरुणाचल प्रदेश में तो कभी लद्दाख में। उनकी चिंता का पूरा फोकस पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार से होने वाली घुसपैठ पर है। मोदी अब तक कु ल 12 मर्तबा बतौर पीएम लाल किले से भाषण दे चुके हैं तो उनमें से शुरू के 11 बार उनके भाषण में घुसपैठ की समस्या का कोई जिक्र नहीं हुआ। पहली बार घुसपैठ का जिक्र उन्होंने अपने 12वें भाषण में किया। जाहिर है कि राम मंदिर, अनुच्छेद 370, समान नागरिक संहिता के बाद पैदा हुए खालीपन को भरने के लिए एक नए मुद्दे की तलाश थी, जो घुसपैठ पर जाकर खत्म हुई है। हालांकि झारखंड के चुनाव में यह मुद्दा बेअसर रहा है लेकिन भाजपा ने हार नहीं मानी है। उसे मालूम है कि राम मंदिर और अनुच्छेद 370 के मुद्दों को भी दशकों तक सींचने के बाद वोटों की फसल लहलहाई है। इसलिए वह घुसपैठ का मुद्दा भी पूरे जोर–शोर से उठाती रहेगी। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और असम में भी इसे आजमाया जाएगा। इन तीन राज्यों के चुनावों को ध्यान में रखकर ही इस मुद्दे को चुना गया है। सवाल है कि सरकार क्या सचमुच घुसपैठ की समस्या का समाधान करना चाहती है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि पिछले 11 साल से केंद्र में लगातार भाजपा की सरकार है और अभी तक उसकी ओर से घुसपैठ रोकने का एक भी गंभीर प्रयास होता नहीं दिखा है। अमित शाह पिछले छह वर्षों से देश के गृह मंत्री हैं। इस बात का खूब ढिंढोरा पीटा जाता है उन्होंने सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है। अलबत्ता गृह मंत्री के रूप में उनकी नाकामियों की कोई चर्चा नहीं होती है। हालांकि पिछले दिनों एक अखबार के कार्यक्रम में भाषण देते हुए अमित शाह बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को रोकने में तो अपनी नाकामी खुद कु बूल कर चुके हैं। उन्होंने कहा, श्बांग्लादेश से लगी सीमा पर कई झरने, महासागर जैसी नदियां, बहुत सारी पहाड़ियां और विशाल जंगल हैं, जहां बाड़ नहीं लगी है और वहां से घुसपैठ कोई नहीं रोक सकता।श बांग्लादेश की सीमा से होने वाली घुसपैठ के लिए 11 साल पहले की यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है और पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला किया जाता है कि वह जमीन नहीं दे रही है। माना कि बंगाल सरकार जमीन नहीं दे रही है लेकिन सवाल यह है कि असम और त्रिपुरा से लगी सीमाओं पर बाड़ लगाने में क्या समस्या है? असम में 10 और त्रिपुरा में भी आठ साल से भाजपा की सरकार है। वहां डबल इंजन की सरकारें होने के बावजूद बांग्लादेश से लगी। सीमाओं पर बाड़ नहीं लगाई जा सकी है और इंसानों से लेकर पशुओं तक की तस्करी जारी है। पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में भाजपा या उसके गठबंधन की सरकारें हैं लेकिन म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या घुसपैठियों को नहीं रोका जा सका है।

मध्य एशिया में भारत की पकड़ ढीली हुई, खाली करना पड़ा ताजिकिस्तान में स्थित एयरबेस

नीरज

भारत अब ताजिकिस्तान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण आयनी (।लदप) एयरबेस का संचालन नहीं करता, जिसे उसने 2002 से विकसित और संयुक्त रूप से संचालित किया था। यह जानकारी हाल ही में सार्वजनिक हुई है, किंतु सूत्रों के अनुसार भारत ने 2022 में ही इस बेस से पूरी तरह वापसी कर ली थी। हम आपको बता दें कि भारत और ताजिकिस्तान के बीच यह सहयोग एक लीज अनुबंध पर आधारित था, जिसकी अवधि 2021 में समाप्त हो गयी थी। ताजिकिस्तान ने संभवतः रूस और चीन के दबाव के कारण इसे आगे बढ़ाने से इंकार कर दिया था। इसके बाद भारत ने अपने सैन्य कर्मियों और उपकरणों को वहां से हटा लिया। हालाँकि वहाँ भारत की कोई स्थायी वायुसेना तैनाती नहीं थी, लेकिन दो–तीन हेलीकॉप्टर जो भारत ने ताजिकिस्तान को भेंट किए थे, वह भारतीय वायुसेना के कर्मियों द्वारा मानवतावादी और राहत अभियानों में संचालित किए जाते थे। कभी–कभी ैन–30 डज्ञप् लड़ाकू विमानों की अस्थायी तैनाती भी वहां की गई थी। हम आपको बता दें कि आयनी एयरबेस (जिसे गिस्सार मिलिट्री एयरोड्रोम– ळड। भी कहा जाता है) ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से पश्चिम में स्थित है। इसे भारत ने लगभग दो दशक तक विकसित किया और इसके विस्तार पर लगभग 100 मिलियन डॉलर खर्च किए। यह वही ठिकाना था जहाँ से भारत ने 2001 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अपने नागरिकों की निकासी में भी सहायता ली थी। भारत ने इस बेस को अपनी सामरिक पहुँच के रूप में उपयोग किया था, विशेषकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दिशा में। देखा जाये तो भारत की आयनी एयरबेस से वापसी, सिर्फ एक कूटनीतिक या प्रशासनिक घटना नहीं है, यह दक्षिण और मध्य एशिया की भू–राजनीतिक संरचना में एक गहरा परिवर्तन है। यह निर्णय ऐसे समय सामने आया है जब मध्य एशिया, विशेष रूप से ताजिकिस्तान, रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव में है और भारत की वहाँ की सामरिक पकड़ कमजोर होती जा रही है। हम आपको बता दें कि आयनी एयरबेस भारत की "कनेक्ट सेंट्रल एशिया" नीति का केंद्रबिंदु था। 2001 में अफगानिस्तान संकट के बाद जब पाकिस्तान के रास्ते भारत की पहुँच अवरुद्ध थी, तब ताजिकिस्तान में यह एयरबेस भारत की एकमात्र ऐसी संपत्ति थी जिससे वह अफगान मामलों और उत्तरी दिशा के रणनीतिक परिदृश्य में सक्रिय रह सकता था। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीस और वर्तमान एनएसए अजीत डोभाल जैसे रणनीतिक मस्तिष्कों ने इसे भारत की "फॉरवर्ड पॉलिसी" का हिस्सा बनाया था। इसके 3,200 मीटर लंबे रनवे ने भारतीय वायुसेना को यह क्षमता दी थी कि वह न केवल अफगानिस्तान बल्कि पाकिस्तान के उत्तरी ठिकानों (जैसे पेशावर) तक अपनी पहुंच बना सके। हम आपको बता दें कि ताजिकिस्तान की सुरक्षा और आर्थिक संरचना रूस पर काफी हद तक निर्भर है। रूस के 201वें सैन्य डिवीजन की वहाँ स्थायी तैनाती है और चीन ने भी ताजिकिस्तान में सीमा–पुलिस और खुफिया ठिकानों के माध्यम से अपनी पकड़ मजबूत की है। ऐसे में भारत का एक स्वतंत्र सैन्य ठिकाना, रूस–चीन दोनों के लिए सामरिक असुविधा बन गया था। रूस नहीं चाहता था कि भारत या कोई अन्य "गैर–क्षेत्रीय शक्ति" मध्य एशिया में स्वतंत्र सैन्य उपस्थिति बनाए रखे। दूसरी ओर, चीन ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के वाखधन कॉरिडोर को अपनी पश्चिमी सुरक्षा–पट्टी के रूप में देखता है। इस क्षेत्र में भारतीय गतिविधि, उसे "स्ट्रैटेजिक इनक्लोजमेंट" का आभास देती थी। देखा जाये तो आयनी एयरबेस से भारत की वापसी का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि अब भारत की "नॉर्थ–वेस्टर्न डिफेंस एक्सटेंशन" पूरी तरह समाप्त हो गई है। पाकिस्तान के साथ संभावित दो–फ्रंट स्थिति (पूर्वी और पश्चिमी मोर्चा) में भारत को जो सामरिक बढ़त मिल सकती थी, वह अब खो चुकी है। अब भारत की वायुसेना को कश्मीर और लद्दाख के बेसों से ही पश्चिमी अभियानों की योजना बनानी होगी, जबकि ताजिकिस्तान से ऑपरेशन की स्थिति में पाकिस्तान को पश्चिम से दबाव झेलना पड़ता। आयनी एयरबेस से वापसी यह भी दर्शाती है कि भारत की मध्य एशिया में भू–आर्थिक पहुँच सीमित है। चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ–साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर (प्छैज्) जैसी परियोजनाओं के बावजूद भारत ताजिकिस्तान या उज्बेकिस्तान तक कोई सुरक्षित लॉजिस्टिक चौनल स्थापित नहीं कर सका। इस विफलता ने भारत को क्षेत्रीय गठबंधनों में एक सीमित भागीदार बना दिया है, जबकि चीन अपने ठमसज ंदक त्वंक प्दपजपंजपअम के जरिए वहाँ स्थायी प्रभाव बना रहा है। आगे का रास्ता क्या हो, यदि इसको देखें तो सबसे पहले तो भारत को इस घटना को पराजय के रूप में नहीं, बल्कि रणनीतिक पुनर्संरचना के अवसर के रूप में देखना चाहिए। भारत ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्त के साथ संयुक्त प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और मानवीय परियोजनाओं के माध्यम से अपनी उपस्थिति बनाए रख सकता है। इंटेलिजेंस साझेदारी और काउंटर–टेररिज्म सहयोग के नए प्रारूप भारत को पुनः प्रभावी भूमिका दे सकते हैं। साथ ही, ईरान के माध्यम से वैकल्पिक पहुँच मार्ग (जैसे चाबहार से मध्य एशिया तक कॉरिडोर) को त्वरित गति देनी होगी। बहरहाल, आयनी एयरबेस का खोना भारत की सामरिक सीमाओं की याद दिलाता है कि केवल निवेश और तकनीक से भू–राजनीति नहीं चलतीय इसके लिए स्थायी गठबंधन, राजनीतिक प्रभाव और लॉजिस्टिक क्षमता आवश्यक है। भारत यदि मध्य एशिया में अपनी जगह पुनः बनाना चाहता है, तो उसे केवल सैन्य दृष्टिकोण नहीं, बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक त्रिकोणीय रणनीति अपनानी होगी। आयनी से वापसी एक अध्याय का अंत है, पर यह भारत की "उत्तर दिशा" की कहानी का अंतिम पृष्ठ नहीं है।

तमाम सभ्यताओं का जन्म नदियों के किनारे ही हुआ

डॉ. विभा नायक

नदियां किसी भी संस्कृति का प्राण तत्त्व हैं। विभिन्न संस्कृतियों के जन्म और उनके विकास का आधार यही नदियाँ हैं जो अपने अमृत से अपनी संततियों में जीवन रस का संचार करती हैं। विश्व का इतिहास साक्षी है कि तमाम सभ्यताओं का जन्म नदियों के किनारे ही हुआ है। नदियों के निकट की उर्वर भूमि, जल की निरंतर उपलब्धता, प्राकृतिक संपदा और संसाधन और इन सबसे प्रभावित और संतुलित ऋतु चक्र के कारण ही सभ्यताओं को फलने–फूलने के लिए सबसे उत्तम स्थान नदियों के किनारे ही मिला। यही कारण है कि प्रकृति एवं पंच शक्ति पूजक हम भारतीयों के लिए नदी केवल जल की एक धारा मात्र नहीं रही, बल्कि वह उस विराट मातृ शक्ति का रूप भी है, जिसका कार्य ही है अपनी संततियों का पालन और पोषण करना। किन्तु आज की स्थितियों में हम पाते हैं कि हमने नदियों से लिया तो बहुत कुछ है किन्तु बदले में उन्हें हम कुछ दे नहीं पाए हैं, सिवाय अस्वच्छता के। भारत में 200 से अधिक छोटी बड़ी नदियाँ हैं। कुछ आँकड़ों के अनुसार यह संख्या 400 के आस पास है। जिनमें कुछ मुख्य और कुछ सहायक नदियाँ हैं तो कुछ छोटी और बरसाती नदियाँ हैं। इन नदियों का धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से बड़ा महत्व रहा है। कुम्भ स्नान, गणोश चतुर्थी, कार्तिक स्नान, मकर संक्रांति में डुबकी और छठ पर्व के अतिरिक्त विभिन्न धार्मिक स्थलों पर भी नदियों की पूजा और उनमें डुबकी लगाने का विधान है, शुभ कार्यों, पूजन के भोग और पंचामृत में गंगा जल का क्या महत्व है, इससे तो सभी परिचित ही हैं तो मोक्ष प्राप्ति के लिए सनातन काल से अस्थि विसर्जन भी इन्हीं नदियों में ही होता आया है। सीधा सा अर्थ है कि भारतीय नदियों का संबंध भारत की सनातन चेतना, परंपरा और आस्था से तो है ही औद्योगिक और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी इनका बहुत महत्व है। किन्तु विगत कुछ वर्षों में देखा गया है कि तीव्र गति से हो रही जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक विकास, घरेलू एवं कृषि क्षेत्र में बढ़ते दबावों के कारण जल की मांग अत्यधिक बढ़ी है, जिससे पेय जल की समस्या का संकट खड़ा तो हुआ ही है, जल की गुणवत्ता में भी कमी आई है। हमारी नदियाँ तीव्र गति से प्रदूषित हो रही हैं। विभिन्न खतरनाक तत्व जिसमें अमोनिया, नाइट्रेट और फॉस्फेट जैसे उर्वरक, डिटर्जेंट, तेल और हाइड्रोकार्बन, कैडमियम, पारा, सीसा जैसे रासायनिक कचरे, स्टायरोफोम, प्लास्टिक और पोलीथिन सम्मिलित हैं, नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार प्रतिदिन 60 प्रतिशत से अधिक अशोधित जल भी सीधे नदियों में जाता है। सीधी सी बात है कि नदियों में बढ़ते प्रदूषण का यह स्तर न केवल नदी की जैविकी को नुकसान पहुँचा रहा है बल्कि आम जन–जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। हालांकि भारत सरकार द्वारा नदियों के लिए कई योजनाएँ भी चलाई जा रही हैं जिनमें राष्ट्रीय नदी संरक्षण, गंगा एक्शन प्लान, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नमामि गंगे, यमुना सफाई अभियान प्रमुख हैं किन्तु ये योजनाएँ तभी सफल हो सकती हैं, जबकि लोक चेतना और उसमें भी नारी शक्ति उससे जुड़ी हो। संभवतरू इसी विचार से जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2023 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के अवसर पर स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान का आरंभ किया। जिसका आदर्श वाक्य है– जीवन के लिए पानी का सम्मान। चूँकि जल प्रबंधन का कार्य घरों में महिलाएँ ही संभालती हैं। जल के महत्व और उसका प्रबंधन स्त्रियाँ बहुत कुशलता से करती हैं, अतरू जल संरक्षण का कार्य महिलाओं को सौंपा जाना सही दिशा में उठाया गया कदम है। इस संबंध में सबसे अच्छी बात यह है कि इस योजना का उद्देश्य जल संरक्षण के क्षेत्र में स्त्रियों की भागीदारी को मान्यता देना, उन्हें जमीनी स्तर से आगे लाकर राष्ट्रीय नेतृत्व से जोड़ना और इस प्रकार दूसरों को जल सुरक्षित भविष्य से जोड़ने का क्रांतिकारी विचार भी सम्मिलित है। इसी योजना के अंतर्गत 36 महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। इस संबंध में राष्ट्रपति डॉ द्रौपदी मुर्मू का कथन है कि– देश में स्वच्छता अभियान और स्वच्छ पेय जल जैसी लोगों से जुड़ी देशव्यापी योजनाओं की सफलता में देश की महिला शक्ति की भूमिका अहम है और इस अभियान का आधार नारी है। इसी योजना के अन्तर्गत महिलाओं को प्रशिक्षित और जागरूक भी किया जा रहा है, जिसका असर जमीनी स्तर पर भी देखा जा रहा है। ग्रामीण अंचलों में भी देखें तो महिलाएँ प्लास्टिक और पॉलिथीन के प्रयोग से बचने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही हैं। प्लास्टिक की बोतलें जो जल और समग्र प्रकृति के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हैं, महिलाएँ उनसे गुलदस्ते बनाकर कर स्व–रोजगार को भी बढ़ावा दे रही हैं। इसी प्रकार ग्रे वाटर प्रबंधन की व्यवस्था, जिससे नालियों से निकलने वाला पानी पीने के पानी को दूषित न करे और जल स्रोतों की स्वच्छता सुनिश्चित हो, इस दिशा में भी महिलाएँ बड़ी संख्या में आगे आ रही हैं। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों जैसे यमुना की स्वच्छता में भी दिल्ली की मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कई स्वयं सेवी संस्थान जिनमें बड़ी संख्या में स्त्रियाँ भी हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। केवल इतना ही नहीं स्त्रियों के नेतृत्व में नदियों और जल प्रबंधन से सबंधित और भी कार्य हो रहे हैं, जिसका एक उदाहरण हैं भारतीय वैज्ञानिक डॉ नीलिमा गुप्ता, जिन्होंने लगभग चार दशक से अधिक समय तक गंगा नदी के प्रदूषण पर शोध करके प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, डब्लूडब्लू एफ, एनजीटी को अपने शोध से परिचित कराया और इससे सम्बद्ध कई परियोजनाएँ भी संचालित कीं। नदियों में बढ़ते प्रदूषण की समस्या पर उनका कहना है कि नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण परजीवी बढ़ रहे हैं। जलीय जीवन इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जिसका कुप्रभाव पर्यावरण और स्वास्थ्य के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। इसी प्रकार सी टू सोर्स गंगा नदी अभियान में भारत और बांग्लादेश में गंगा नदी में प्लास्टिक प्रदूषण का अध्ययन करने वाली महिला टीम भी महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य भी नदियों विशेषकर गंगा में बढ़ते प्रदूषण और उसके कारण समुद्र में निरंतर बढ़ते प्लास्टिक और अन्य प्रकार के कचरे की ओर ध्यान दिलाना है, जिसके कारण पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय जीव बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो नदियों की सुरक्षा और स्वच्छता की दिशा में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। किन्तु यह भी सच है कि यह अभी आरंभिक चरण में ही है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि स्त्री किसी भी परिवार और समाज की धुरी होती। सभी पर्व और त्योहारों के केंद्र में भी स्त्री की ही भूमिका रहती है, तो ऐसे में सामाजिक और राष्ट्रहित से जुड़े विषयों में स्त्री यदि नेतृत्वकारी भूमिका में आती है तो निश्चय ही इसका स्वागत होना चाहिए और प्रयास यह भी होना चाहिए कि जल संरक्षण और प्रकृति से जुड़े विषयों में स्त्रियों की भागीदारी और बढ़ सके।

समूह क और ख के पदों की शैक्षिक अर्हता तय, व्यापारियों को जेल भेजने वाले 13 कानून खत्म

लखनऊ, (संवाददाता)। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में समूह क और समूह ख के पदों की शैक्षिक अर्हता में बदलाव के प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी मिल गई है। दरअसल, जिला कार्यक्रम अधिकारी के सात और बाल विकास परियोजना अधिकारी के 22 पदों पर सीधी भर्ती से चयन होना है। इसके लिए समकक्ष शैक्षिक अर्हता स्पष्ट न होने से उप्र लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजने में बाधा आ रही थी। विभाग ने संशोधन कर इसे स्पष्ट कर दिया है। अब जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए किसी विवि से समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, गृह विज्ञान या समाज कार्य में से किसी भी विषय में स्नातक की

उपाधि होनी चाहिए। बाल विकास परियोजना अधिकारी पद के लिए समाजशास्त्र, समाज कार्य या गृह विज्ञान में स्नातक की अर्हता तय की गई है। प्रदेश सरकार ने उद्योग और व्यापार जगत के लिए बड़ा कदम उठाते हुए "उत्तर प्रदेश सुगम व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश–2025" को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में मंगलवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए पारित इस अध्यादेश के तहत राज्य में लागू 13 प्रमुख औद्योगिक व व्यापारिक अधिनियमों में लगभग 99 प्रतिशत आपराधिक प्रावधान समाप्त कर दिए गए हैं। अब अधिकांश मामलों में उद्यमियों और व्यापारियों को जेल भेजने की बजाय आर्थिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था लागू होगी। यह कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा और प्रदेश में निवेश का माहौल और अनुकूल बनेगा। इस अध्यादेश के तहत कई पुराने प्रावधान, जिनमें मामूली उल्लंघन पर भी कारावास का प्रावधान था, अब हटाए जा रहे हैं। छोटे–मोटे तकनीकी उल्लंघनों पर अब जुर्माना या चेतावनी दी जाएगी। अध्यादेश के दायरे में आने वाले प्रमुख अधिनियमों में फैक्ट्री अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, बोइलर अधिनियम, और अनुबंध श्रमिक अधिनियम शामिल हैं। इन सभी में ऐसे प्रावधानों को संशोधित किया गया है जो निवेशकों के लिए अनावश्यक बाधा पैदा करते थे। नई व्यवस्था में लाइसेंस व पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा, जिससे अनावश्यक कार्यालयी चक्कर खत्म होंगे।

वित्तीय गड़बड़ी की जानकारी के बाद भी दबाई जा रही रिपोर्ट

लखनऊ, (संवाददाता)। लखनऊ विश्वविद्यालय के निर्माण विभाग में वित्तीय गड़बड़ी की जानकारी होने के बावजूद विवि प्रशासन सच्चाई दबाने में जुटा है। मामले की शिकायत के बाद गुपचुप जांच हुई और फिर निर्माण विभाग के अधीक्षक पद पर तैनात प्रो. डीके सिंह ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। जबकि मामले की शिकायत कुलपति, कुलसचिव, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उच्च शिक्षा मंत्री तक से की गई है।

अभी तक अधिकारिक तौर पर जांच कमेटी का गठन नहीं हुआ। विवि के प्रवक्ता प्रो. मुकुल श्रीवास्तव ने मंगलवार को बताया कि मामले में अभी ऊपर से कोई निर्देश नहीं आया है। बता दें कि कि छात्र नेता कार्तिक पांडेय की ओर से 27 सितंबर को शिकायत दर्ज कराई गई थी। 29 सितंबर को भी विद्युत उपकेंद्र से फार्मेसी संस्थान भवन तक केबल और ट्रांसफॉर्मर लगाने के काम में कुल 83 लाख 84 हजार 785 रुपये के गबन का आरोप लगाया था।

संक्षिप्त खबरें

सीआईटीएस के 16 टॉपर्स को किया सम्मानित

लखनऊ, (संवाददाता)। सिर पर उपलब्धियों का सेहरा, चेहरे पर सफलता की मुस्कान के साथ दीक्षांत परिधान में पहुंचे कुशल प्रशिक्षण मेधावियों को देश में सर्वश्रेष्ठ होने का प्रमाण मिला। मौका था मंगलवार को अलीगंज स्थित प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केंद्र (आईटीओटी) में दीक्षांत समारोह का। व्यावसायिक शिक्षा मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस) के 16 मेधावियों को सम्मानित करते हुए शुभकामनाएं दीं। आईटीओटी के निदेशक डीके सिंह ने बताया कि वर्ष 2015 में तीन व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स के साथ कारवां शुरू हुआ थ। अब 10 व्यावसायिक कोर्स में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 10 वर्ष पहले परिसर में छात्र–छात्राओं की संख्या 300 थी। अब 1300 से अधिक विद्यार्थी हर साल सकुशल प्रशिक्षण ले रहे हैं। कंपनियों की मांग के अनुरूप पाठ्यक्रम और नए उभरते क्षेत्रों में कुशल प्रशिक्षकों की मांग पर एक और दो वर्षीय न्यू एज कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इनमें इलेक्ट्रिक वाहन मैकेनिक, उन्नत सीएनसी मशीनिंग तकनीशियन, बेसिक डिजाइनर और वर्चुअल वेरिफायर कोर्स शामिल हैं। उन्नत उपकरण का उपयोग करने वाले कारीगर, औद्योगिक रोबोटिक्स और डिजिटल विनिर्माण तकनीशियन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीशियन, औद्योगिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स व विनिर्माण प्रक्रिया नियंत्रण और स्वचालन से जुड़े नए पाठ्यक्रम शामिल हैं।

संस्कृत, संगीत व सांकेतिक भाषा विषय में दूर होगी शिक्षकों की कमी

लखनऊ, (संवाददाता)। डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में स्नातक संस्कृत, संगीत सहित सांकेतिक भाषा से जुड़े विषयों में शिक्षकों की कमी जल्द दूर होगी। विवि की ओर से 26 पदों पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय की ओर से विज्ञापन जारी कर एक सप्ताह तक आवेदन लिए जाएंगे। फिर साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। विवि का दावा है कि पूरी प्रक्रिया 10 से 12 दिनों में पूरी होगी। गेस्ट फैकल्टी के आने से विद्यार्थियों की नियमित क्लास चल सकेगी और मौजूदा शिक्षकों पर से काम का बोझ कम होगा। बता दें कि इससे पहले 40 पदों पर तैनाती की जानी थी, जिसमें 14 पद भरे जा चुके हैं। विवि में स्नातक संस्कृत की पढ़ाई इसी सत्र से शुरू हुई है। 60 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है, लेकिन शिक्षक न होने के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विवि की ओर इस समस्या का निदान पिछले माह ही किया जाना था। पुनर्वास विश्वविद्यालय के प्रवक्ता प्रो. यशवंत वीरोदय के अनुसार, 24 गेस्ट फैकल्टी की तैनाती के लिए विज्ञापन जल्द ही जारी किया जाएगा। इसके बाद एक सप्ताह तक आवेदन लिए जाएंगे। फिर साक्षात्कार कर तैनाती की जाएगी।

अनुपम व फारूकी को सृजन सम्मान

लखनऊ, (संवाददाता)। यूपी प्रेस क्लब व उप्र साहित्य सभा की ओर से मंगलवार को प्रेस क्लब में 162वां सृजन सम्मान समारोह हुआ। कार्यक्रम में हसीब सिद्दीकी, सर्वेश अस्थाना व शिवशरण सिंह ने वरिष्ठ शायर वासिफ फारूकी को सृजन उर्दू व अनुपम श्रीवास्तव को सृजन हिंदी सम्मान दिया।

कृषि नीति में होगा बड़ा बदलाव, अब प्रदेश में खुलेंगी निजी किसान मंडियां

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश में किसानों को उनकी उपज का ज्यादा मूल्य दिलाने की नई रणनीति बनाई गई है। इसके तहत निजी क्षेत्र की मंडियों की स्थापना के लिए नियमों का सरलीकरण किया जाएगा। जमीन का क्षेत्रफल घटाने के साथ ही प्रतिभूति रकम, परियोजना लागत भी कम करने की तैयारी है। आधारभूत सुविधाओं के विस्तार में सरकार कई तरह की सहूलियतें दे सकती है। दरअसल, बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार निजी क्षेत्र में मंडियों की स्थापना पर जोर दे रही है। इसके लिए 2019 में उप्र. कृषि उत्पादन मंडी (21वां) संशोधन नियमावली भी बनाई गई है। इसके तहत 17 प्रमुख नगरों में लाइसेंस शुल्क दो लाख रुपये व अन्य स्थानों पर शुल्क एक लाख रुपये रखा गया। लेकिन निजी निवेशकर्ता आगे नहीं आए। इसे देखते हुए कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग अन्य राज्यों में स्थापित निजी मंडियों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करा रहा है। निजी क्षेत्र में मंडी स्थापना के लिए अभी बड़े शहरों के लिए परियोजना लागत 10 करोड़ और दो हेक्टेयर भूमि का मानक है लेकिन इतनी जमीन शहरी इलाके में नहीं मिल पा रही है। प्रतिभूति राशि भी ज्यादा है। इसे देखते हुए अब जमीन और प्रतिभूति राशि के मानक में भी कटौती की तैयारी है। सरकार भी निवेशकों को कई तरह सुविधाएं देने पर विचार कर रही है। निजी मंडी स्थल पर नीलामी हॉल, शेड्स, दुकानें, गोदाम, भंडारण, कैंटीन, प्रयोगशाला, पैकेजिंग, लोडिंग एवं अनलोडिंग स्थल, पेजयल, सड़क सहित कई तरह की व्यवस्थाएं जरूरी होती हैं। इसमें भूमि हस्तांतरण के दौरान स्टांप, बिजली, पेयजल आदि की सुविधाएं सरकार की ओर से देने पर विचार चल रहा है। बता दें, प्रदेश में अभी 249 विनियमित मंडियां और 356 उप मंडियां हैं। 10 करोड़ परियोजना लागत वाले स्थलों में आगरा, लखनऊ, कानपुर, बरेली, बाराबंकी, वाराणसी, ललितपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, शाहजहांपुर, लखीमपुर, गाजियाबाद, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, मुरादाबाद और सहारनपुर शामिल है। पांच करोड़ की परियोजना में जिला मुख्यालय व अन्य स्थल हैं। विभाग को लागत मूल्य कम करने और नियमों में छूट देने से इस क्षेत्र में निजी निवेशकों के आने की उम्मीद है। निजी क्षेत्र की मंडियां स्थापित होने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। बाजार के लिए प्रतिस्पर्धा जरूरी होता है। इसका फायदा किसानों को मिलेगा। जहां ज्यादा लाभ व सुविधाएं मिलेंगी किसान वहां जाएंगे। निजी मंडी शुरू होने से वहां प्रसंस्करण, शीतगृह सहित अन्य सुविधाएं भी मिल सकेंगी। भविष्य के लिहाज से यह बेहतर कदम होगा।

सामाजिक संगठनों ने थाना घेरा, बोले-बीमार नहीं...अपराधी है पुलिस पर जताया गुस्सा

लखनऊ, (संवाददाता)। काकोरी पेशाब कांड को लेकर बुधवार को काकोरी कस्बे में आक्रोश भड़क उठा। कई सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने काकोरी थाने का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा, आरोपी पम्मू गुप्ता बीमारी का नाटक कर अस्पताल में ऐश कर रहा है, जबकि उसे जेल में होना चाहिए। संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने थाने परिसर में ही धरना देकर पीड़ित रामपाल को न्याय दिलाने की मांग उठाई। थाने पर देर तक नारेबाजी होती रही और माहौल तनावपूर्ण बना रहा। काकोरी क्षेत्र के हाता हजरत साहब वार्ड में हुई घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यहां मंदिर परिसर में बैठे बुजुर्ग रामपाल रावत (65) के साथ केयरटेकर स्वामिकांत गुप्ता ने अमानवीय व्यवहार किया। आरोप है कि आरोपी ने बुजुर्ग पर मंदिर परिसर में पेशाब करने का झूठा आरोप लगाते हुए न सिर्फ जातिसूचक गालियां दीं, बल्कि पानी को पेशाब बताकर जबरन चटवाया।

घटना से आहत बुजुर्ग ने जब यह बात अपने परिजनों को बताई तो वे तत्काल थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मामला सामने आने के बाद न केवल लखनऊ, बल्कि पूरे देश में इस अमानवीय कृत्य को लेकर गुस्से की लहर दौड़ गई। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों ने बुजुर्ग के पक्ष में आवाज उठाई और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बृहस्पतिवार को कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित रामपाल रावत से मिलने उनके घर पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में बाराबंकी सांसद तनुज पुनिया, पूर्व विधायक इंदल कुमार रावत, जिला अध्यक्ष रुद्रदमन सिंह चौहान, महानगर अध्यक्ष डॉ. शहजाद आलम, अमित श्रीवास्तव, पूर्व प्रवक्ता प्रदेश सचिव सचिन रावत, एससी–एसटी प्रकोष्ठ की सरलेश रावत और सिद्धिश्री रावत शामिल रहे।

संक्षिप्त खबरें

दिव्यांग छात्रों को मिलेंगे अब और गुणवत्तापूर्ण उपकरण

लखनऊ, (संवाददाता)। डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे दिव्यांग छात्रों को अब और सुविधाजनक गुणवत्तापूर्ण उपकरण मिल सकेंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय के विशेष शिक्षा संकाय व बौद्धिक अक्षमता विभाग और मेरठ सेना अस्पताल के बीच एमओयू होगा। मंगलवार को पुनर्वास विश्वविद्यालय विशेष शिक्षा संकाय व बौद्धिक अक्षमता विभाग के प्रमुख डॉ. कौशल शर्मा सेना अस्पताल मेरठ पहुंचे। उन्होंने आशा स्कूल का निरीक्षण किया और वहां के शिक्षकों व कर्मचारियों से बातचीत की। अस्पताल की ओर से डॉ. कौशल को सम्मानित किया गया। अस्पताल के कमांडेंट ब्रिगेडियर विक्रम पात्रा एमओयू का प्रस्ताव रखा।

आजाद इंजीनियरिंग कॉलेज की संबद्धता निरस्त करने की शासन से संस्तुति

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी में सरोजनीनगर के नटकुर में चारागाह की जमीन कब्जा करके बनाए जाने के मामले में अब डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) ने भी सख्ती की है। एकेटीयू की संबद्धता समिति ने आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की संबद्धता निरस्त करने की संस्तुति शासन को भेजी है। कुलपति प्रो. जेपी पांडेय की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई आकस्मिक संबद्धता समिति की बैठक में कॉलेज का मामला रखा गया। समिति को अवगत कराया गया कि उक्त मामले में राजस्व परिषद ने कॉलेज के खिलाफ निर्णय लिया है। साथ ही सरकारी जमीन कॉलेज के कब्जे से वापस लेने का निर्णय लिया है। कुलपति प्रो. पांडेय ने बताया कि इसी क्रम में समिति ने कॉलेज की संबद्धता निरस्त करने की संस्तुति की है। उन्होंने इसे संस्तुति के लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग को भेजा है। वर्तमान में एकेटीयू से कॉलेज की इंजीनियरिंग और फार्मेसी की संबद्धता है। इसे निरस्त किया गया है। उन्होंने कहा कि शासन की संस्तुति के बाद यहां पढ़ रहे छात्रों को उनके पास के अन्य कॉलेजों में भेजकर कोर्स पूरा कराया जाएगा। छात्रों के भविष्य से किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। बता दें कि राजस्व परिषद ने कॉलेज की ओर से कब्जा की गई जमीन को वापस चारागाह में दर्ज कर लिया है।

आईएफडब्ल्यूजे ने मनाया 75 वां स्थापना दिवस अयोध्या सम्मेलन मे पत्रकारों का होगा जमावड़ा

लखनऊ, (संवाददाता)। यूपी प्रेस क्लब में आज इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई । यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन फेडरेशन की प्रादेशिक इकाई है, जिसके अध्यक्ष हसीन सिद्दीकी ने बताया कि देश के इस पहले पत्रकार संगठन का गठन आज ही के दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर किया गया था । तब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फेडरेशन को सहयोग के रूप में सौ रुपए का चेक दिया था। इन 75 वर्ष में संगठन के पूर्वजों और उनके अनुवर्ती पदाधिकारियों ने लगातार संघर्ष कर संगठन को एक पहचान दी। देश–दुनिया में संगठन का महत्व बनाया। पहला वेज बोर्ड भी पत्रकारों के वेतन के लिए बना। के विक्रम राव साहब के नेतृत्व ने संगठन को नयी ऊंचाई दी।

कहीं वाह गोमती... कहीं आह गोमती

लखनऊ, (संवाददाता)। लक्ष्मण मेला घाट, दिन 27 अक्तूबर, समय रू शाम 4:30 बजे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां आयोजित छठ मेला महोत्सव में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के बाद कहा था कि गोमती व घाटों की सफाई की जिम्मेदारी सभी नागरिकों की भी है। नागरिकों के राष्ट्रीय कर्तव्य से जुड़े बिना देश विकसित नहीं हो सकता, इसलिए सभी का योगदान अपेक्षित है कि वे सफाई का ध्यान रखें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि एक से डेढ़ वर्ष में प्रयास होगा कि कोई ड्रेनेज या सीवर गोमती में नहीं गिरेगा। पीलीभीत से गाजीपुर तक नदी निर्मल व अविरल होगी। लक्ष्मण मेला घाट, दिन रू 28 अक्तूबर, समय रू शाम 3:57 बजे। जिस जगह पर मुख्यमंत्री ने खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया था, उस जगह पर पूजन सामग्री व पॉलिथीन समेत गंदगी का ढेर था। दोपहर 1:13 बजे इस घाट के मुख्य द्वार पर सफाई करते कर्मचारी नजर आए थे, लेकिन शाम को जब दोबारा यहां पहुंचकर तफ्तीश की गई तो घाट पर गोमती के किनारे गंदगी पड़ी मिली और सफाई कर्मचारी नदारद थे। यही हाल संझियाघाट पर भी दिखा, जहां दोपहर 12:45 बजे कर्मचारी सफाई करते दिखे। शाम 4:28 बजे दोबारा इस घाट पर जाकर तफ्तीश की गई तो घाट से लेकर गोमती तक में गंदगी के ढेर नजर आ रहे थे। आखिर ये कैसी आस्था है जो सिर्फ पर्व तक सीमित रहती है। इसके बाद हम नागरिक अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। छठ पर एक दिन पहले तक जहां स्वच्छ बहती गोमती के किनारे के घाट चमक रहे थे, वहां दूसरे दिन गंदगी का अंबार लगा था। पूजन सामग्री, पॉलिथीन और अन्य गंदगी गोमती के पानी से लेकर घाट तक बिखरी थी। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभी नागरिकों से की गई अपील का यह हश्र दिखा। हालांकि, झूलेलाल घाट, पंचवटी घाट और कुड़ियाघाट समेत कुछ स्थानों पर मुख्यमंत्री की अपील का असर दिखा, जहां स्वच्छता का ध्यान रखा गया। मैं तुम्हारी गोमती हूं... अभियान के संयोजक सुशील सीतापुरी और शुभ संस्कार समिति के महामंत्री रिद्धि किशोर गौड़ ने कहा कि गोमती, इसके घाटों को स्वच्छ रखना है तो सरकार, प्रशासन का सहयोग करने के लिए आम नागरिकों को आगे आना होगा। सभी के सम्मिलित प्रयास से ही हम स्वच्छता अभियान को सफल बना सकते हैं। नगर निगम के जोनल अधिकारी मनोज यादव ने बताया कि जहां मंगलवार को सफाई नहीं हो पाई, वहां बुधवार को काम कराया जाएगा।

देव दीपावली पर काशी बनेगी 'मिनी भारत', घाटों पर झलकेगी देश की विविध सांस्कृतिक छटा

लखनऊ, (संवाददाता)। देव दीपावली पर जब संपूर्ण काशी गंगा तट पर लाखों दीपों की रोशनी में नहाएगी, तब यह प्राचीन नगरी एक बार फिर "मिनी भारत" की झलक पेश करेगी। इस बार की देव दीपावली न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक होगी, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता का भव्य उत्सव भी बनेगी। गंगा किनारे जगमगाते दीप इस बार देश के अलग–अलग हिस्सों की परंपराओं और रीति–रिवाजों का जीवंत चित्र बनेंगे।प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस वर्ष हर घाट अपनी विशिष्ट पहचान के साथ अलग–अलग संस्कृतियों का रंग बिखेरेगा। कहीं मराठी परंपरा की झलक दिखेगी, तो कहीं दक्षिण भारत की रीतियाँ, मैथिल ब्राह्मणों द्वारा दीपों की सजावट, गुजराती रंगोली और थालियों की साज–सज्जा विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगी। काशी की देव दीपावली इस बार "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" की भावना को साकार करती नजर आएगी और देश–विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं व पर्यटकों के लिए नया अनुभव बनेगी।पर्यटन मंत्री ने बताया कि काशी के पंच तीर्थों में से एक पंचगंगा घाट पर इस बार भी मराठी संस्कृति की अनूठी छटा दिखाई देगी। मराठी मोहल्ले के परिवार पारंपरिक ढंग से दीप सज्जा और गंगा आरती की तैयारियों में जुटे हैं। वहीं, पास स्थित नेपाली मोहल्ले के परिवार अपनी पारंपरिक शैली में दीये जलाकर गंगा तट को रोशन करेंगे। इन दोनों संस्कृतियों का संगम देव दीपावली की रात पंचगंगा घाट को विशेष बनाएगा।गौरीकेदार घाट पर दक्षिण भारतीय संस्कृति का रंग बिखरेगा। यहां गौरी केदारेश्वर मंदिर परिसर में दीप सज्जा, भक्ति संगीत और पारंपरिक पूजा की तैयारियाँ जोरों पर हैं। दक्षिण भारत से आए परिवारों की भागीदारी से यह घाट दक्षिण भारतीय परंपराओं का केंद्र बनेगा।इसी प्रकार पुराने गुजराती मोहल्ले में भी दीप सज्जा शुरू हो चुकी है। चौक, ठठेरी बाजार और मणिकर्णिका के आसपास के मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। गुजराती समुदाय पारंपरिक परिधान में पूजा–अर्चना करेगा और रंगोली से सजे दीयों की थालियाँ इलाके की शोभा बढ़ाएँगी। वहीं, दशाश्वमेध और राजेंद्र प्रसाद घाट पर मैथिल ब्राह्मणों की पूजा–पद्धति से दीप प्रज्ज्वलन किया जाएगा। इस बार इन घाटों की सजावट ऐतिहासिक पैमाने पर होगी। जब देव दीपावली की रात गंगा के दोनों तट लाखों दीपों से आलोकित होंगे, तब यह दृश्य केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता का अद्भुत उत्सव होगा।पर्यटन मंत्री ने कहा कि देव दीपावली भारत की आत्मा का उत्सव है। काशी के घाटों पर देश की हर संस्कृति की परंपरा एक साथ दमकती है। मराठी, दक्षिण भारतीय, गुजराती, मैथिल और नेपाली परंपराओं का यह संगम काशी को 'मिनी भारत' बना देता है।

स्मार्ट मीटर ने काटा विद्युत सखियों के रोजगार का कनेक्शन

लखनऊ, (संवाददाता)। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू हुई विद्युत सखी योजना कभी ग्रामीण अंचलों में महिला सशक्तीकरण की मिसाल मानी जाती थी। प्रशिक्षण प्राप्त कर महिलाओं ने गांव–गांव जाकर बिजली बिल जमा कराने का जिम्मा उठाया था। इस काम से वे न केवल आत्मनिर्भर बनीं, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में भी अहम भूमिका निभाई।

हर माह 18 से 30 हजार रुपये तक कमाने वाली ये महिलाएं अब परेशान हैं, क्योंकि घर–घर लग रहे स्मार्ट मीटर ने इनके रोजगार का कनेक्शन काट दिया है। अब बिजली बिल खुद उपभोक्ता ऑनलाइन जमा कर रहे हैं, जिससे विद्युत सखियों की आय घटकर मात्र 4–5 हजार रुपये रह गई है। कई स्थानों पर तो पूरी तरह काम ठप हो गया है। जिले की करीब 180 विद्युत सखियां पिछले करीब छह महीने से अब बेरोजगारी की चिंता में हैं। मलिहाबाद के गुसवां निवासी व कमल स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष शशि गुप्ता अनुसार, 2022 से विद्युत सखी के रूप में काम कर रही हूं। शुरुआत में लोगों का भरोसा जीतने में वक्त लगा। अब जब सब ठीक चल रहा था, स्मार्ट मीटर लगने से आमदनी पांच हजार पर आ गई है, वह भी कब बंद हो जाए पता नहीं।

ग्राम बेहटा निवासी ओम स्वयं सहायता समूह की अध्यक्षा शशि रावत ने बताया कि पति ड्राइवर हैं। मैंने जनवरी 2022 से काम शुरू किया था और 25 हजार रुपये तक कमा लेती थी। स्मार्ट मीटर आने से सारा काम बंद हो गया है। शासन को पहले कोई वैकल्पिक रोजगार देना चाहिए था। उपायुक्त स्वतरू रोजगार, अजीत कुमार सिंह ने बताया कि जिले में करीब 180 विद्युत सखियां हैं। स्मार्ट मीटर लगने के बाद वे एप के माध्यम से बिल जमा नहीं कर पा रहीं हैं। मामला शासन के संज्ञान में है, जल्द ही उन्हें वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

घुमंतू व सपेरा समाज की समस्याओं पर राज्यमंत्री असीम अरुण ने दिया समाधान का भरोसा

लखनऊ, (संवाददाता)। समाज के वंचित वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से डबल इंजन की सरकार लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में घुमंतू समुदाय से जुड़े सपेरा समाज के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण से भेंट कर अपनी विभिन्न मूलभूत समस्याओं से अवगत कराया।सपेरा समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्हें अभी भी बिजली, पानी, शौचालय, पेंशन और अंतिम संस्कार के लिए स्थान जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव झेलना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी मांग रखी कि जिन परिवारों के पास कृषि भूमि नहीं है, उन्हें सरकारी योजनाओं के तहत पट्टा दिलाया जाए ताकि वे भी मुख्यधारा से जुड़ सकें।राज्यमंत्री असीम अरुण ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाज के उत्थान के प्रति बेहद संवेदनशील हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ''घुमंतू विकास मिशन'' के अंतर्गत समुदायों का चिन्हीकरण कर आधार, जाति और आय प्रमाणपत्र बनवाए जाएंगे ताकि पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। इसके साथ ही कार्यक्रम की नियमित मॉनिटरिंग कर कार्य प्रगति पर नजर रखी जाएगी।राज्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन परिवारों के पास भूमि नहीं है, उनकी स्थिति का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ताकि उन्हें उनका अधिकार मिल सके। बैठक में सपेरा समाज से सूरजनाथ, राजकुमार, हिंदलनाथ, राजेन्द्रनाथ सहित ।

एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत लखनऊ में 140 पौधे लगाए गए

लखनऊ, (संवाददाता)। "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के अंतर्गत मंगलवार को जोन 8 के विद्यावती द्वितीय वार्ड स्थित सेक्टर जी की ग्रीन बेल्ट में भव्य पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री और लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की। उनके साथ लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल और वार्ड के पार्षद कौशलेंद्र द्विवेदी भी उपस्थित रहे।कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना और मातृत्व के सम्मान में प्रत्येक परिवार को एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित करना था। पौधारोपण के दौरान मंत्री सुरेश खन्ना और महापौर सुषमा खर्कवाल ने टिकोमा का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। भाजपा पार्षद दल के उपनेता सुशील तिवारी श्पम्मीश, पार्षद कौशलेंद्र द्विवेदी, भाजपा नेता सौरभ सिंह श्मोनूश, हिमांशु अंबेडकर, सुनील मिश्रा, मिशन सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाराम अंबेडकर और नगर निगम अधिकारियों ने भी अशोक का पौधा लगाकर अभियान में भागीदारी निभाई।कार्यक्रम के तहत कुल 140 पौधे लगाए गए, जिनमें अशोक, टिकोमा, कनेर, आम और आंवला के पौधे शामिल थे। पौधों की नियमित देखभाल और सिंचाई की जिम्मेदारी भी तय की गई, ताकि ये पौधे विकसित होकर शहर की हरियाली को बढ़ा सकें।कार्यक्रम में नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। सभी ने "एक पेड़ मां के नाम" अभियान की सराहना करते हुए इसे मातृत्व सम्मान और पर्यावरण संरक्षण का अद्भुत संगम बताया।महापौर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि यह अभियान न केवल पर्यावरण को हरा–भरा बनाने की दिशा में एक कदम है।

फूड कलर और तंबाकू का सेवन लोगों में कैंसर का सबसे बड़ा कारण

सिटी रिपोर्टर प्रत्यूष पाण्डेय

लखनऊ। मेदांता अस्पताल के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग द्वारा कैंसर सर्वाइवर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस अवसर पर कई कैंसर सर्वाइवर्स ने अपनी कहानियां साझा कीं, जिससे अन्य मरीजों को नई उम्मीद और हिम्मत मिली। साथ ही विशेषज्ञों ने बताया कि कैंसर अब लाइलाज नहीं रहा। अगर इसका पता शुरुआती चरण में चल जाए तो अधिकांश मामलों में मरीज पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। कार्यक्रम में डॉ. नीरज रस्तोगी, डायरेक्टर, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, डॉ. मोहम्मद सुहैब, डायरेक्टर, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, डॉ. रेशम श्रीवास्तव एसोसिएट डायरेक्टर, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और डॉ नीलेश अग्रवाल, एसोसिएट कंसलटेंट रेडिएशन ऑकोलॉजी उपस्थित रहे। विशेषज्ञों ने बताया कि पुरुषों में लगभग 40 प्रतिशत और महिलाओं में करीब 15 प्रतिशत कैंसर का कारण तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला जैसी चीजों का इस्तेमाल करना है। इन आदतों को छोड़कर भारत में

करीब 40 प्रतिशत कैंसर के मामलों को रोका जा सकता है। मुंह, गले, फेफड़े के कैंसर के अलावा पेशाब की थैली और पैंक्रियाज का कैंसर भी तंबाकू का इस्तेमाल करने से होता है। इसके अलावा खाने में इस्तेमाल होने वाले आर्टिफिशियल फूड कलर भी कैंसर के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। महिलाओं में होने वाला सबसे सामान्य स्तन कैंसर है, जिसे महिलाएं तीन स्टेप में सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के माध्यम से पहचान सकती हैं। मेदांता ने महिलाओं को जागरूक करने के लिए इस एग्जामिनेशन से जुड़ा एक वीडियो जारी किया है, जो ऑनलाइन उपलब्ध है। साथ ही, मेदांता कैंप भी आयोजित कर रहा है, जहाँ प्रशिक्षित नर्सों द्वारा टॉर्सो मॉडल के माध्यम से महिलाओं को स्वयं परीक्षण करने की प्रक्रिया सिखाई जा रही है। अगर कैंसर की पहचान पहली या दूसरी स्टेज में हो जाए, तो 80 से 90 प्रतिशत मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। तीसरी स्टेज में लगभग 50 प्रतिशत और चौथी में 15 प्रतिशत तक मरीज पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। कैंसर से बचाव के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और फलों–सब्जियों का सेवन जरूरी है। इनसे शरीर को प्राकृतिक विटामिन मिलते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। डॉक्टर्स का मानना है कि इलाज में सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी का कॉम्बिनेशन सबसे असरदार माना गया। ज्यादातर मरीज छह महीने के भीतर सामान्य जीवन में लौट आते हैं। मेदांता के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. राकेश कपूर ने कहा, "कैंसर का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, ।

बदलापुर महोत्सव–2025 की तैयारी हेतु बैठक सम्पन्न

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर विधायक बदलापुर रमेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में सल्तनत बहादुर इण्टर कॉलेज, बदलापुर में बदलापुर महोत्सव–2025 मनाए जाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में विधायक ने विभागवार तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान किए। उन्होंने बताया कि पूर्व की भांति इस बार भी महोत्सव ऐतिहासिक रूप से मनाया जाएगा। उन्होंने निर्देशित किया कि सामूहिक विवाह हेतु मंडप, जोड़ों के बैठने की व्यवस्था, उनके पहचान पत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्टॉल और प्रदर्शनी लगाने, मेधावी छात्रों का सम्मान सहित

ट्रैफिक व्यवस्था, पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाने, संबंधित सभी आवश्यक तैयारियाँ समय से पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, परियोजना निदेशक के. के. पांडेय, उप जिलाधिकारी बदलापुर योगिता सिंह, क्षेत्राधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

संक्षिप्त खबरें

मैक्स हॉस्पिटल, लखनऊ, ने अयोध्या में शुरू की ब्रेस्ट कैंसर की विशेष ओपीडी सेवाएं

अयोध्या (प्रत्यूष पाण्डेय).पूर्वी उत्तर प्रदेश में कैंसर इलाज की सुविधाओं को और सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ, ने अयोध्या में अपनी विशेष ब्रेस्ट कैंसर ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की। यह सेवा शहर के देवा मेमोरियल मेडिकल, सर्जिकल एंड मैटर्निटी नर्सिंग होम के सहयोग से शुरू की गई है। इस विशेष ओपीडी सेवा का शुभारंभ डॉ. फाराह अरशद, एसोसिएट डायरेक्टर दृ ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सर्जरी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, लखनऊ, की उपस्थिति में हुआ। डॉ. फाराह अरशद, अब हर महीने के तीसरे गुरुवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक देवा मेमोरियल मेडिकल, सर्जिकल एंड मैटर्निटी नर्सिंग होम, देवकली रोड, अयोध्या, में मरीजों को परामर्श देने और फॉलो–अप के लिए मौजूद रहेंगी।

14 कोसी परिक्रमा पर नाका पर भी तैनात रहे पुलिस कर्मियों के साथ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी

अयोध्या। गुरुवार को भोर से हो रही दोपहर तक अनवरत बारिश के बावजूद भी 14 कोसी परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी।वहीं सुरक्षा की दृष्टि से शहर की हनुमानगढ़ी के समीप पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद रहे।इस मौके पर यूपी उपजिलाधिकारी

सोहावल सुनीता,जिला समाज कल्याण अधिकारी,सीओ रुदौली आशीष निगम,सीओ शशि प्रकाश मिश्रा,थानाध्यक्ष रुदौली संजय मौर्या,थानाध्यक्ष महाराजगंज राजेश सिंह सहित कई पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों के साथ भ्रमण शील रहे।इस मौके पर एसडीएम सोहावल सुनीता तथा रुदौली आशीष निगम ने संयुक्त रूप से बताया की डीएम व एसएसपी के निर्देश पर श्रद्धालुओं की सुविधा में कोई कोताही नहीं की जा रही है।वहीं तीन जगह पर सीसीटीवी कैमरे तथा बीडीएस कर्मियों के माध्यम से भी आसपास की चेकिंग कराई जा रही है।इसके अलावा हनुमानगढी के पास अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार पाण्डेय ने दमकल कर्मियों के साथ किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद रहे।

राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभभाई पटेल - अम्बरीष कुमार सक्सेना

हरदोई(ए के सक्सेनाध्वीरेश श्रीवास्तव)

शिव सत्संग मण्डल के राष्ट्रीय समन्वयक अम्बरीष कुमार सक्सेना के अनुसार सरदार वल्लभभाई पटेल भारतीय इतिहास के ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जिन्हें "लौह पुरुष" और "राष्ट्रीय एकता के शिल्पकार" के रूप में जाना जाता है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आजाद भारत के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता झवेरभाई पटेल एक साधारण किसान थे और माता लाडबाई धार्मिक विचारों वाली थीं। बचपन से ही सरदार पटेल में अनुशासन, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय की भावना थी।

उन्होंने वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड से की और भारत लौटकर एक सफल वकील बने। परंतु देशभक्ति की भावना ने उन्हें गांधीजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदानरू–

सरदार पटेल ने किसानों के अधिकारों के लिए खेड़ा सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। बारदोली आंदोलन की सफलता के बाद उन्हें "सरदार" की उपाधि दी गई। वे कांग्रेस के प्रमुख नेता बने और स्वतंत्रता संग्राम में गांधीजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लगभग 562 रियासतें थीं। सरदार पटेल ने अपनी कुशल नीति, दृढ़ता और कूटनीति से इन रियासतों का भारत संघ में विलय कराया। यह कार्य असंभव प्रतीत हो रहा था, परंतु उनके साहस और दूरदर्शिता ने इसे संभव बना दिया। इसी कारण उन्हें "भारत का बिस्मार्क" कहा जाता है। सरदार पटेल का पूरा जीवन अनुशासन, दृढ़ संकल्प और देश की एकता के लिए समर्पित रहा। उन्होंने देशहित को हमेशा सर्वोपरि माना। उनकी स्मृति में गुजरात के केवड़िया में विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा "स्टैच्यू ऑफ यूनिटी" स्थापित की गई है, जो भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। सरदार वल्लभभाई पटेल का जीवन हमें यह सिखाता है कि एकता में ही शक्ति है। वे सच्चे अर्थों में भारत की एकता, अखंडता और समरसता के प्रतीक हैं। उनका जीवन और विचार सदैव हमें प्रेरित करते रहेंगे।

राज्य सरकार द्वारा गन्ने के मूल्य में रू. 30 प्रति कु. तक की बढ़ोत्तरी से किसानों में खुशी

हरदोई (अम्बरीष कुमार सक्सेना) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में गन्ना मूल्य वृद्धि करने के ऐतिहासिक फैसले से किसानों में खुशी की लहर है। राज्य सरकार के निर्णय अनुसार, गन्ने के मूल्य में रू. 30 प्रति कु. तक की बढ़ोत्तरी की है। नए पेराई सत्र 2025–26 में अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य रू. 400 प्रति कु. होगा, जबकि सामान्य प्रजाति के लिए यह दर रू. 390 प्रति कु. तय की गई है, गन्ना मूल्य वृद्धि से प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। जिससे गन्ना किसानों की आय में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। केन ग्रोवर्स सोसाइटी हरदोई के अध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह ने राज्य सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने के मूल्य में वृद्धि की घोषणा की है। अब अगैती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य 390 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।राज्य सरकार का यह निर्णय किसानों के हित में लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा गन्ना मूल्य में हुई इस वृद्धि से प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। चीनी मिल डीसीएम श्रीराम लि., शुगर यूनिट – लोनी के क्षेत्रीय किसानों में राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में लिये गये ऐतिहासिक फैसले से खुशी की लहर दौड़ गई है जिसका आभार व्यक्त करते हुये चीनी मिल क्षेत्र कृषक एवं समाजसेवी पंकज सिंह (हुसैनापुर धौकल), भाजपा नेता अक्षय प्रताप सिंह, लवलेश सिंह, शिवमोहन दीक्षित (ग्रा0–उधरनपुर), श्री सन्तराम (ग्रा0–सरदारनगर), रवि शंकर शुक्ला (ग्रा0–उधरनपुर), रूद्रप्रताप सिंह (ग्रा0–गढेघ्पुर), अनुराग शुक्ला (ग्रा0–उधरनपुर), प्रेम कुमार (ग्रा0– शर्मा), राजीव कुमार सिंह (ग्रा0–मंझिला), हरिओम मिश्रा (ग्रा0–उधरनपुर), विजयकांत मिश्रा (ग्रा0–उधरनपुर), डा0 तौहीद–प्रधान (ग्रा0–टुमुर्की), डा0 तौकीर–प्रधान (ग्रा0–हर्रई), अनिल कुमार (ग्रा0–बहेरवा हासिमपुर), मन्दीप सिंह (ग्रा0–पैंगुसराय), बुधपाल (ग्रा0–टेडवा), अनिल कुमार त्रिवेदी

संक्षिप्त खबरें

एसपी ग्रामीण ने व्हीलचेयर से महिला श्रद्धालु को कराया मार्ग पार

अयोध्या।14 कोसी परिक्रमा के दौरान सिर्फ युवा वर्ग ही नहीं बल्कि बूढ़े बुजुर्ग यहां तक की दिव्यांग भी परिक्रमा करते हुए देखे जा रहे थे।जिसमें कुछ ऐसे भी श्रद्धालु 14 कोसी परिक्रमा करते हुए दिखाई दिए जो चलने में तथा मार्ग पार करने में असमर्थ दिखाई दे रहे थे।इसी बीच में एक महिला जो की मार्ग नहीं पर कर पा रही थी उसे एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने व्हील चेयर की सहायता से मार्ग पार कराया।कुल मिलाकर चौदह कोसी परिक्रमा के दौरान अयोध्या में श्रद्धा, सेवा और मानवीय संवेदना का सुंदर संगम देखने को मिला।परिक्रमा में एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी द्वारा की गई इस संवेदनशील पहल व पुलिस की मानवता और सेवा भावना का वास्तविक उदाहरण बताया।

गौ माता में समस्त देवी–देवताओं का निवास है, और उनकी सेवा से जीवन धन्य होता है : डॉ सुभाष

ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

पॉलिटेक्निक चौराहे के पास स्थित कृषि भवन के अस्थाई गौशाला परिसर में गोपाष्टमी महापर्व बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर गौ सेवक पवन मिश्रा जी के नेतृत्व में गायत्री महायज्ञ एवं गौ पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में, जिला संघ चालक डॉक्टर सुभाष सिंह जी सपरिवार उपस्थित रहे, माननीय विभाग संयोजक गौ सेवा विभाग काशी प्रांत श्री शैलेंद्र उपाध्याय जी सपरिवार, जिला गौशाला संपर्क प्रमुख विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा विभाग अवधेश मौर्य जी व गौ सेवक डॉक्टर अमरनाथ पांडे जी, प्रमोद शुक्ला जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप तिवारी द्वारा किया गया। धर्माचार्य त्रिभुवन नाथ पांडे जी एवं शिवनारायण मिश्रा जी ने वैदिक विधि–विधान से गायत्री महायज्ञ व गौ पूजन सम्पन्न कराया। इस दौरान गौ सेवक पवन मिश्र के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं मातृशक्ति उपस्थित रही कृ जिनमें गौ सेविका रश्मि जी अपनी माता जी के साथ और डॉ प्रियंका गुप्ता जी सह परिवार, सुनील शर्मा जी, खुशवंत जी, शिवाजी, अंकुश जी, एस. जी., आयुष जी, सुमित जी, श्रेया जी, अमन जी, शुभम जी सहित अनेकों गौ भक्तों ने भाग लिया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने हवन, गौ आरती के पश्चात गौशाला के गोवंशों को पालक, पत्ता गोभी, केला एवं गुड़ प्रेमपूर्वक खिलाया। इस अवसर पर डॉ. सुभाष सिंह जी ने अपने उद्बोधन में कहा हम सबको अपने जीवन के हर शुभ अवसर कृ जैसे पूर्वजों की पुण्यतिथि, बच्चों के जन्मदिन, विवाह वर्षगाँठ आदि पर गौशाला में उपस्थित होकर गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता में समस्त देवी–देवताओं का निवास है, और उनकी सेवा से जीवन धन्य होता है।" अंत में गौ सेवक पवन मिश्रा जी ने सभी अतिथियों एवं सहयोगी भाइयों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए यह संकल्प दिलाया कि हम सभी गौ भक्त जीवन पर्यन्त गौ सेवा व गौ संरक्षण के कार्यों में निरंतर सक्रिय रहेंगे और निराश्रित गोवंश की सेवा को अपना परम धर्म मानेंगे।

सराफा दुकान से भारी भरकम तिजोरी उठा ले गए चोर, तीन लाख से अधिक के जेवर चोरी

पीलीभीत, (संवाददाता)। पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र में रम्पुरा मिश्र चौराहा स्थित सराफा दुकान में घुसे चोर भारी भरकम तिजोरी ही उठा ले गए। बुधवार को सुबह लोगों ने तिजोरी दुकान

से करीब पांच सौ मीटर दूर गन्ने के खेत में पड़ी देखी तो वे हैरान रह गए। जानकारी करने पर पता चला कि यह तिजोरी संतोष गंगवार की सराफा दुकान से चोरी की गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और सीओ सदर आईपीएस नताशा गोयल ने जांच की। जांच में पता लगा कि चोर शटर के कुंडे काटकर दुकान में घुसे थे। ताले उसी में लटकते मिले। बरेली के थाना नवाबगंज क्षेत्र के गांव गूलड़ डांडी निवासी संतोष गंगवार की रम्पुरा मिश्र चौराहे पर सराफा दुकान है। उन्होंने बताया कि मंगलवार की शाम वह दुकान बंद कर घर चले गए। रात के समय चोरों ने दुकान में धावा बोला। दुकान में रखी तिजोरी उठा ले गए। सुबह उन्हें सूचना मिली तो तुरंत मौके पर आ गए। दुकान स्वामी के अनुसार, चोर करीब 3.50 लाख रुपये का सामान समेट ले गए हैं। पुलिस आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। एक जनसेवा केंद्र पर लगे सीसीटीवी कैमरे में चार संदिग्ध नजर आए हैं। बाद में इन संदिग्धों ने डंडे से कैमरे को ऊपर कर दिया, जिससे वह दुकान से तिजोरी लेकर जाते नहीं दिखे। वहीं चोरी की इस घटना से लोग हैरान हैं। चोर भारी भरकम तिजोरी उठाकर आधा किमी तक ले गए और किसी को भनक तक नहीं लगी।

दंगल में चार पहलवान जीते दो मुकाबले बराबरी पर छूटे

पीलीभीत, (संवाददाता)। रामलीला मेले में चल रहे दंगल में कुश्ती के छह मुकाबले हुए। इनमें चार पहलवान जीते। दो मुकाबले बराबरी पर छूटे। मंगलवार को पहला मुकाबला बाबर पहलवान दिल्ली और राजवीर पहलवान राजस्थान के बीच हुआ। इसे बाबर ने जीता। दूसरा मुकाबला चिमचिम डोगरा भूटान और तूफान पहलवान झांसी के बीच हुआ। इसमें चिमचिम डोगरा जीते। तीसरा मुकाबला अमीरा पहलवान जहानाबाद और हसीन बौना पहलवान कलियर शरीफ के बीच हुआ। इसमें अमीरा विजयी रहे। चौथा मुकाबला पंडित थापा पहलवान नेपाल और चंद्र मुखी पहलवान के बीच हुआ। इसमें पंडित थापा को जीत मिली। पांचवां मुकाबला मुन्ना पहलवान गोरखपुर और चिम चिम डोगरा के बीच बराबरी पर रहा। छठा मुकाबला शैतान सिंह पहलवान गोरखपुर और मनोज पहलवान तिलहर बीच भी बराबरी पर रहा। रेफरी की जिम्मेदारी अमजद पहलवान और पंडित शास्त्री पहलवान ने निभाई। जीतने वाले पहलवानों को पुरस्कृत किया।

गैरहाजिर अधिकारियों का स्पष्टीकरण तलब

पीलीभीत, (संवाददाता)। सीएम डैशबोर्ड की बैठक में प्रतिभाग न करने पर डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने प्रोजेक्ट मैनेजर और एई आवास विकास का स्पष्टीकरण तलब किया है। साथ ही बैठक में मौजूद लोगों को निर्देश जारी किए कि वह गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य कराते हुए समय से कार्यों को पूरा कराए। मंगलवार को कलक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में 50 लाख से अधिक लागत के निर्माण कार्यों को लेकर सीएम डैशबोर्ड की बैठक हुई। समीक्षा के दौरान निपुण परीक्षा, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, कन्या विवाह सहायता योजना और फैमिली आईडी की समीक्षा हुई। उन्होंने फैमिली आईडी के लक्ष्य को शत–प्रतिशत पूर्ण करने व अन्य योजनाओं में प्रगति लाने के निर्देश दिए। विभागों की ओर से निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की गई। जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी ने ललौरीखेड़ा, मरौरी एवं बीसलपुर में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय निर्माण, दूनी बैराज का निर्माण, ब्रहमचारी घाट पर्यटन विकास कार्य, नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, ड्रग वेयरहाउस निर्माण की प्रगति, पानी की टंकी की जलापूर्ति हेतु नल कनेक्शन एवं नई सड़कों के निर्माणध्चौड़ीकरणध्सुदृढ़ीकरण आदि परियोजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया। डीएम ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य जल्द पूरा कराए जाए। साथ ही पूरे हो चुके निर्माण कार्यों को हैंडओवर करें।

चार निकायों में एमआरएफ ठप, कचरे में लगा रहे आग

भदोही, (संवाददाता)। जिले के सात में से चार नगर निकायों ज्ञानपुर, सुरियावां, घोसिया और नई बाजार में कचरे का निस्तारण कागजों पर किया जा रहा है। करीब दो करोड़ रुपये खर्च कर बनाए गए मैटीरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) सेंटर शोपीस बने हैं। दूसरी ओर सुरियावां और घोसिया नगरों में कचरे के निस्तारण के बजाय जलाकर प्रदूषण और बीमारियों को न्योता दिया जा रहा है। चारों निकायों में हर दिन औसतन 30 से 35 टन कचरा निकलता है। ज्ञानपुर में एक महीने से बिजली की तकनीकी खामी से सेंटर बंद पड़ा है। जिले में भदोही और गोपीगंज नगर पालिका और ज्ञानपुर, सुरियावां, घोसिया, खमरिया एवं नई बाजार नगर पंचायतें हैं। नगर निकायों में कचरे के निस्तारण के लिए एमआरएफ सेंटर बनाए गए हैं। हर निकाय में लगभग 50 लाख रुपये एमआरएफ सेंटर के निर्माण पर खर्च किए गए हैं। जहां गीला और सूखा कचरा अलग करने के साथ ही कचरे से खाद बनाने की भी सुविधा है। निकायों में कागजों पर तो एमआरएफ सेंटर खूब दौड़ रहे हैं लेकिन हकीकत इससे जुदा है। मंगलवार को एमआरएफ सेंटरों की पड़ताल में पता चला कि सुरियावां के शहीद नगर वार्ड 12 नगर में पांच साल पहले एमआरएफ सेंटर बनाया गया। नगर में रोज 10 से 12 टन कचरा निकलता है, जिसे सेंटर के पास लाकर रख दिया जाता है। मगर, यहां कूड़े को जला दिया जाता है। तीन साल पहले घोसिया में बने एमआरएफ सेंटर को अब तक चालू नहीं किया जा सका है। यहां मशीन तो रखी है लेकिन कचरे को जलाकर निस्तारित किया जाता है। नईबाजार के एमआरएफ सेंटर में ताला लगा रहा। दूसरी तरफ खमरिया में गीला और सूखा कचरा अलग तो किया जाता है लेकिन उसका निस्तारण कैसे किया जाता है, यह जिम्मेदार नहीं बता सके। ज्ञानपुर में दो महीने से सेंटर बिजली न होने से बंद है। घोसिया और सुरियावां में कचरे का निस्तारण तो नहीं कराया जा सका है लेकिन उसमें आग लगा दी जा रही है। इससे एक तरफ कचरे से निकलने वाले प्रदूषित धुएं से पूरा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। वहीं प्लास्टिक आदि के जलने से आसपास के लोगों की सेहत पर भी इसका असर पड़ रहा है। जिले के सात निकायों में करीब 80 से 85 टन कचरा निकलता है। इसमें चार निकायों में 30 से 35 टन कचरा रोज निकलता है।

5.50 करोड़ से सुधरेगी डीघ रजबाहा की सेहत

भदोही, (संवाददाता)। मुख्य नहर से जुड़े डीघ रजवाहा का पानी अब टेल तक पहुंचेगा। 17 किमी लंबी नहर के तीन से चार किमी दायरे को पक्का कराया जाएगा। इसके अलावा क्षतिग्रस्त पुलिया और फाल को भी दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए नहर विभाग ने 5.50 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इससे 10 से 15 गांवों के करीब 15 से 20 हजार किसानों को सिंचाई का सीधे लाभ मिलेगा। ज्ञानपुर मुख्य नहर प्रयागराज के केहुनी से निकलकर वाराणसी और मिर्जापुर जिले तक जाती है। इसकी लंबाई 74 किमी है। इससे तीन रजबाहे जुड़े हैं। इसमें डीघ रजबाहा करीब 17 किमी, भदोही रजबाहा की लंबाई 53 और सीखड़ रजबाहा की लंबाई 43 किमी है। तीनों जिलों में करीब ढाई से तीन लाख किसानों को इसका लाभ मिलता है। डीघ रजबाहा से डीघ ब्लॉक क्षेत्र की फसलों की सिंचाई होती है। इसमें कुछ माइनर और कुलाबे भी बने हैं। गंगा तटीय इलाका होने से डीघ रजबाहा के टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता। तीन से चार किमी पहले ही बलुई मिट्टी होने से पानी सूख जाता है। इससे कटरा, धनतुलसी समेत 10 से 15 गांवों के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता।

कांग्रेस की बढ़ती ताकत से दिखेगा बदलाव - राय

सीतापुर, (संवाददाता)। शहर के राजा कॉलेज मैदान में मंगलवार को कांग्रेस पार्टी की ओर से संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सांसद राकेश राठौर की अगुवाई में हुए इस आयोजन की जिम्मेदारी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हिस्सेदारी करते हुए कहा कांग्रेस की बढ़ती ताकत से जल्द देश में बदलाव दिखेगा। इसकी शुरूआत बिहार चुनाव से होगी। बारिश होने के बावजूद कार्यक्रम में जुटे कार्यकर्ता की भीड़ को देख कर प्रसन्न प्रदेश अध्यक्ष ने इसे कांग्रेस की बढ़ती ताकत का संकेत बताया। कहा कि सीतापुर में कांग्रेस की बढ़ती ।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।